पर यहां बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि भूपेन्द्र सिंह मान हरेक आदमी जानता कि यह कृषक समाज से जुड़े हुए हैं और कृषकों के हक में आन्दोलन करते आए हैं। इन आन्दोलनों को और बिना किसी स्वार्थ के इस काम को देखते हुए राष्ट्रपति ने इनको इस सदन में मनोनीत किया है। यह राष्ट्रपति के नोमिनेटेड मैम्बर हैं और उसके बावजूद उस राष्ट्रपति के नोमिनेटेड मैम्बर का एक कांस्टेबल जा कर कहता है कि तुम चलो थाने में, डी० एस० पी० बताएगा तुम्हें कि क्या गिरफ्तारी, तुम्हारे खिलाफ क्या केस है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। यह पूरे देश के राष्ट्रपति का मनोनीत सदस्य और उसके साथ इतनी बड़ी धक्काशाही की जाये। यह बर्दाश्त के बाहर है। महोदया, यह रोज आए दिनों देखा जाता है कि यह पुलिस वाले एक कांस्टेबल की ताकत आई० जी० (पुलिस) से ज्यादा हो गई है। अगर पुलिस मैनुअल पढ़ा जाए कि एक मैम्बर आफ़ पार्लियामेंट को किस लेवल का आदमी उससे क्वश्चन कर सकता है या किस लेवल का आदमी एक मैम्बर आफ़ पार्लियामेंट से बात कर सकता है, यह इनको, ये नए जितने नौसिखिये जवान सिपाही भर्ती किये जा रहे हैं इनको पढ़ाने की जरूरत है और ये जबरदस्ती में किसी गिरेबान में हाथ डाल लेते हैं। ये अगर मैम्बर आफ़ पार्लियामेंट के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा, यह तो, सोचने की बात है? महोदया, यह एक गम्भीर मसला है और मैं समझता हूं कि पूरा सदन एकमत होकर यह मांग करता है कि प्रिविलेज का मोशन बनाया जाए और कनसर्न्ड आफ़िसर को यहां पर बुलाया जाये।····(व्यवधान)····

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : महोदया, आर० बी० आई० प्रतिभूतियों के घोटाले से संबंधित फ़ैक्ट्स को दबाने की कोशिश कर रही है। उसने बैंक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को एक पत्र लिखा है···(व्यवधान)···

उपसभापति : बैठिए। Just a minute, please. (*Interruptions*)... Now, the House has to be adjourned for lunch. The House is adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at *thirty-two minutes past two of the clock*,

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Now we shall take up Private Members' Business (Resolutions).

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION RE RISING PRICES

श्री मोहम्मद अमीन (पश्चिमी बंगाल) : मोहतरमा वाइस चेयरमेन साहिबा, आपने मुझे जो प्राइवेट मैम्बर्स रेजोलूशन मूव करने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया।

†[شری محمد امین (پچھمی بنگال) :
محترمہ وائس چیئرمین صاحبہ، آپنے مجھے
جو پرائیویٹ ممبرس ریزلیوشن موو کرنے کا
موقع دیا۔ اس کیلئے شکریہ۔]

"This House expresses its deep concern over the continuous rise in prices of all commodities in the country putting the common man in great distress and also over the addition to the inflationary spiral through issue of administrative orders, the latest example of which being the hike in the prices of petroleum products, and urges upon

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

Government to take immediate comprehensive steps to arrest the continuing price rise due to the economic policies, administered price hike and import of consumer items at the behest of the World Bank."

मोहतरमा, अब महंगाई का यह आलम है कि——

"लगी है आग कुछ इस तरह सारे गुलशन में, कि कोई आसियां महफूज रह न पाय।"

मोहतरमा, ऐसे तो जबसे देश आजाद हुआ तब से महंगाई बढ़ती ही जा रही है, लेकिन शुरू में ऐसा हुआ था कि साल, छह महीने में कभी किसी चीज का दाम बढ़ जाता था और अब हाल यह है कि हर महीना, कभी-कभी हर हफ्ता और कभी-कभी हर रोज कुछ न कुछ चीजों का दाम बढ़ जाता है। सरकार कभी-कभी दावा करती है कि देखो, हमने दाम घटा दिया। अभी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था कि इन्फ्लूशन डबल डिजिट से नीचे कर दिया है और अब सिंगल डिजिट पर ला रहे हैं। असल में सिर्फ इतना होता है कि अक्तूबर, नवम्बर, महीना में जब खेतों की पैदावार होती है, नई सब्जी-तरकारी आती है, अनाज आता है तो दाम थोड़ा सा कम होता है। आलू, प्याज, टमाटर तथा अन्य सब्जियों का अगर थोड़ा सा दाम उतर जाता है तो सरकार अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकने लगती है कि देखिये, दाम कम हो गया। मगर उसके दो महीने बाद ही दाम फिर चढ़ जाता है और पिछले साल के हिसाब से अगले साल उसकी सतह काफी ऊंची हो जाती है। यही तमाशा देखने में आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा हिसाब-किताब के जाल में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि जो लोग हिसाब-किताब बनाते हैं उनकी क्या बुनियाद होती है, वह आम लोगों की समझ में नहीं आती। इसीलिए सरकारी मीडिया के ऊपर से अवाम का एतबार उठता जा रहा है, क्योंकि उनका जो अपना जिंदगी का तजुर्बा है यह उनको बताता है कि दाम घट रहा है या बढ़ रहा है। इसलिए अखबार चाहे कुछ भी लिखे, टेलीविजन पर कुछ भी प्रचार किया जाए या गवर्नमेंट कुछ भी कहे वह बात लोगों के दिलों में नहीं उतरती है। मगर उसके बावजूद मैं दो चीजें पेश करना चाहता हूं। एक चार्ट छपा था 26 नवम्बर को हिन्दू अखबार में। इसमें मार्च, 1991 से लेकर अक्तूबर, 1992 का माहवार गोशवारा है। मैं सब नहीं पढ़ता, सिर्फ मार्च, 1991 में क्या पोजीशन थी और अक्तूबर, 1992 में क्या पोजीशन है, यही दो फिगर बताता हूं।

प्राईमरी आर्टिकल्स :

मार्च, 1991 में 195.6 तथा अक्तूबर, 1992 में 237.1, यानी कुल बढ़ा है 41.5 परसेंट।

फ्युएल ग्रुप :

मार्च, 1991 में 188.6 और अक्तूबर, 1992 में 234.9, यानी कुल बढ़ा है 46.3 परसेंट।

मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स।

मार्च, 1991 में 190.1 और अक्तूबर, 1992 में 226.3, यानी कुल बढ़ा है 36.2 परसेंट।

ऑल कमोडिटीज :

मार्च, 1991 में 191.7 और अक्तूबर 1992 में 230.7, यानी 39.7 परसेंट का इजाफा हुआ है।

अगर परसन्टेज निकाला जाये तो देखा जाएगा कि एक साल के अन्दर तकरीबन 24-25 परसेंट दाम बढ़े हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सरकार जब बनी

और जिसको बने हुए अब एक साल पांच महीने हो गये हैं, इतने ही दिनों में कुल मिलाकर चीजों के दाम 24 से 26 परसेंट तक बढ़ गये हैं। मेरे ख्याल में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह बहुत ही अफसोसजनक सूरते हाल है, क्योंकि उस एतबार से सरकारी मुलाजेमीन या मजदूर या मुलाजमत पेशा लोगों के महंगाई भत्ते में उस हिसाब से कोई इजाफा नहीं हुआ और जो लोग बेकार हैं उनका तो सिवाय खुदा के कोई मददगार नहीं है। महंगाई की जो मार उनके ऊपर पड़ती है उससे बचाने वाला कोई नहीं है। सरकार ने इन करोड़ों लोगों को जो बाजार का दाम बढ़ाकर लूटते हैं, उनके रहमोकरम पर छोड़ दिया है।

1991 में लोक सभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के इलेक्शन मेनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने तहरीरी तौर पर यह एलान किया था कि मुल्क के अवाम अगर उन्हें हुकूमत सोंपदे तो वे सौ दिनों के अन्दर महंगाई को नीचे उतार देंगे। यह छपा है उसमें। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। जब इनकी हुकूमत बन गई और मनमोहन सिंह जी फाइनेन्स मिनिस्टर हुए तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह होने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बात का मुल्क के अवाम पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, सियासी पार्टियों के वायदों पर कितना भरोसा रह जायेगा। अखबारों ने उसके बाद कमेंट किया कि ये लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं ये तो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और उसके बाद महंगाई कम करने के ऊपर इनका ध्यान कम रहता है। वह करोड़ों रुपया जो इनका खर्च हुआ है वह वापस कैसे आयेगा इस तरफ इनका ध्यान ज्यादा रहता है। इस तरह की बातें अखबारों में निकलती हैं और इससे मेरे ख्याल में सरकार की क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है।

दूसरा एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। वह है कंज्यूमर प्राईस इंडैक्स का। एक तो मैंने आपको होलसेल प्राईस इन्डैक्स का बताया। कंज्यूमर प्राईस इंडैक्स का हिसाब जो सरकार का है इसमें मैं जून 91 से अक्तूबर, 92 तक का हिसाब दे रहा हूं। जून 91 में ये था 209, जुलाई में हुआ 214, अगस्त में 217, सितम्बर में 221, अक्तूबर में 223, नवम्बर में 225, दिसम्बर में 225, जनवरी, में 92 में 228, फरवरी में 229, मार्च में 229, अप्रैल में 231, मई में 234, जून में 236, जुलाई में 242, अगस्त में 242, सितम्बर में 243, अक्तूबर में 244 यानी इस तरह 209 से 244 पर जाकर यह पहुंच गया। इन दोनों हिसाब से साबित हो जाता है कि चीजों के दाम किस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आज का यह अखबार है "आब्जर्वर"। इसमें अपने सफा 7 पर देखिये क्या तमाशा किया है। "प्राइस इन्डैक्स फाल्स" लिखा हुआ है।

> "New Delhi : The All-India Consumer Price Index for agricultural labourers (base 1960-61—100) decreased by 13 points from September and it stood at 1099 in October, 1992. The rate of inflation computed on the basis of consumer price index for industrial workers fell to 9.42 in October as against 9.98 in September. Despite the fall in inflation, the All-India Consumer Price for industrial workers (base 1992) rose to 242 in October from 243 in the previous month. With the rise in the index, the rupee value dipped to 14.98 paise in October."

अब इसमें एग्रीकल्चरल लेबर का हिसाब एक किस्म का दिया है और वर्कर्स कंज्यूमर्स प्राइस इंडैक्स एक किस्म का और उसके बाद यह मान लिया है कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडैक्स भी बढ़ा है और रुपये का दाम भी घट गया है। सरकार की प्राइस पालिसी, कीमतों की पालिसी क्या है यह अभी तक अवाम की समझ में नहीं आया। कोई पालिसी है भी या नहीं इसलिए कि हमारे देश की जो हालत है, यहां की मिट्टी इतनी जरखेज है, यहां पानी जिस मिकदार में पाया जाता है, मौसमी हालात, कुदरत मेहरबान है, जाड़ा, गर्मी और बरसात की वजह से इतना उम्दा मौसम दुनिया के बहुत कम मुल्कों में होगा और लोग भी मेहनती हैं। सरकार की तरफ़ से जो कम से कम इंतजाम किया जाना चाहिए वह अगर हो तो किसी चीज की यहां कमी नहीं हो सकती।

ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि 190 बरस तक अंग्रेज साम्राज्यवादियों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। आजादी जिस रास्ते पर आई और जिस तरह उन्होंने मुल्क का बंटवारा कर दिया धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, यह तो अपनी जगह अफसोसनाक बात है। इसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगी मगर यहां वो बेइंसाफ़ी हो गई है। मगर उसके बाद जो कुछ करना चाहिए था पाकिस्तान और बंगला देश में क्या हाल है वह छोड़ दीजिए, वह हमारी बहस की चीज नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान में पहला काम जो करना चाहिए था वह था बेसिक लैंड रिफार्म्स, बुनियादी इस्लहाते आराजला, जिसका वायदा भी कांग्रेस के लीडरों ने किया था। आजादी के पहले कांग्रेस का कोई अधिवेशन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस सवाल पर रेजूलेशन पास न किया गया हो कि मुल्क आजाद होगा तो जमींदारी खतम करके तमाम जमीन किसानों में बांटेंगे। लेकिन आजादी आने के इतने दिनों में क्या वह बेसिक लैंड रिफ़ार्म हुए? कानून जरूर बने, मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ कानून बने थे लेकिन उन कानूनों में बहुत सारी खामियां भर दी गईं जमींदारों के लिए जो किसानों को जमीन नहीं दिलाना चाहते थे अदालतों में जाने का रास्ता खोल दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि बेसिक लैंड रिफ़ार्म हो नहीं पाए। जो कुछ हुआ, किसान पहले ही कमजोर था, कुछ नहीं कर पाया। फ़िर भी कुछ आंध्र प्रदेश में हुआ जहां तेलंगाना की इनकलाबी तहरीर चली थी जिसमें हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी निजाम के राज में और जमीनों पर कब्जा किया था। फिर वह जमीन फौजी कार्यवाही के बाद उनसे छीनी गई। कुछ रख पाए, कुछ छीनी गई, काफ़ी कुछ हुआ। अभी रिजर्व बैंक और भारत सरकार का हिसाब यह बताता है कि सारे हिन्दुस्तान में जितनी जमीनों का बंटवारा हुआ उसका 22 फ़ीसदी हुआ है मगरबी बंगाल में, एक रियासत में। इसलिए कि मगरबी बंगाल में बाएं महाज की हुकूमत है। वह अपने महदूद ऐख्तियारात के अन्दर अपने एक उसूल पर चलती है। उसमें खेत मजदूरों, बटाईदारों और गरीब किसानों ने उसका साथ दिया है। मुझे याद है जब वहां पर मुत्तहिद महाज की हुकूमत बनी थी, मैं भी वह मिनिस्टर था, उस वक्त सरकार ने यह कहा किसानों से कि अगर आप इंतजार में बैठे रहे कि सरकार आपको जमीन दे देगी तो आपको जमीन नहीं मिलेगी नहीं। आप जानते हैं सरकार को तो कानून के मुताबिक चलना पड़ता है लेकिन हदबंदी के ऊपर जो भी जमीन है, जो नाजायज तरीके से छिपाकर रखी गई है उस पर किसान संगठित होकर अगर कब्जा करें तो हम आपकी यह मदद जरूर कर सकते हैं कि जमींदार जब थाने में जाएगा तो पहले जैसे पुलिस उसकी मदद करती थी, हम पुलिस को उसकी मदद करने से रोक देंगे। आगे का मामला

आपको लड़कर जीतना पड़ेगा। इतना सहारा मिल गया तो गांव-गांव में किसानों की तहरीक खड़ी हो गई और लोगों को मालूम था कि पांच हजार, दस हजार बीघे जमीन दबाकर वह बैठे थे। इस तरह से पश्चिमी बंगाल में जमीन का बंटवारा हुआ।

मोहतरमा, चार बार बाएं महाज की हुकूमत पश्चिमी बंगाल में बनी। सरमायादाराना निजाम में रहते हुए भी कम्यूनिस्टों को नजारत मिल गई। सारी दुनिया के लोग ताज्जुब यह करते हैं कि ऐसे कैसे हुआ? लोग कैसे जीत जाते हैं? बाज लोग तो इल्जाम यह लगाते हैं कि पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन ठीक से होते नहीं हैं, इसलिए ये लोग जीत जाते हैं। लेकिन खुद इलेक्शन कमीशन सर्टिफ़िकेट दे चुका है कि पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन मूंसफ़ाना और पुरअमन होते हैं। सारे हिन्दुस्तान में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो वह इन बातों की तरफ़ ध्यान नहीं देते कि इस सरकार ने क्या ऐसा किया है कि लोग इनका साथ दे रहे हैं। चौदह बरस में 16 इलेक्शन हो चुके हैं, चार मर्तबा लोकसभा के, चार दफे पंचायतों के और चार दफ़े म्युनिसिपेल्टियों और कारपोरेशन के और इन 16 इलेक्शनों में ही बाएं महाज के उम्मीदवार सफ़ल हुए। इसलिए कि उन्होंने गांवों में किसानों का साथ दिया और कल-कारखानों के मजदूरों के तहरीक की हिमायत की, सरकारी कर्मचारी जब अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं तो उनकी हिमायत की। इसलिए जो जमीन किसानों को मिल गई तो अनाज कुछ सस्ता है। अगर आप पश्चिमी बंगाल और कलकत्ता में तशरीफ़ ले जायें तो आप देखेंगे कि मुल्क के किसी भी शहर से बंगाल में कुछ चीजें सस्ती हैं सरकार के हाथ में तो पूरे मुल्क के दाम कंट्रोल करने के अख्तियार हैं नहीं, न तो माली अख्तियार है न कानूनी। जो महदूद अख्तियार हैं उन्हीं के अन्दर वह काम करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बाकी हिन्दुस्तान में जहां कई रियासतों में गैर-कांग्रेसी हुकूमतें हैं इनको भी लैण्ड रिफार्म करने से किसने रोका। वी० पी० सिंह की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया लैण्ड रिफार्म के मुतल्लिक। जितने क्वानीन बने हुए हैं सारे मुल्क में, उन्होंने दस्तूर में तरमीम करके इन तमाम क्वानीन को दस्तूर की नवीं शैड्यूल्ड के तहत ला दिया। इसी सदन में हम लोगों ने पास किया था ताकि उसके खिलाफ़ अदालत में जाने का रास्ता बंद हो जाए। उससे किसानों को कोई फायदा पहुंचा या नहीं यह अलग बात है। लेकिन यह काम वी० पी० सिंह की गवर्नमेंट ने बड़ी इमानदारी से किया था। उसके नक्शेकदम पर चलकर अगर इस कदम को आगे बढ़ाया जाता तो भी बात बन सकती थी। लेकिन यहां तो कभी बोफोर्स का मामला चल पड़ता है, कभी बैंक स्कैम चल पड़ता है और कभी मन्दिर-मस्जिद चल पड़ता है। लोग इसी में फंस जाते हैं। करोड़ों लोगों को दो वक्त दाल, रोटी नहीं मिलती, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मोहतरमा, गांव में देहात में जाइये तो आप देखेंगे सर्दी में लोग ठिठुर कर मर जाते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो लू लग जाती है। अखबारों में निकलता है कि लू लगने से कितने लोग मरे। जब बरसात का मौसम आता है,

श्री मोहम्मद अमीन

सैलाब आता है तो गांव का गांव बहा कर ले जाता है। गरीब लोगों को किसी भी मौसम में चैन नहीं है। ये सारे मरने वाले कौन-लोग हैं? ये इंताही गरीब हैं और पावर्टी लाइन के नीचे रहकर जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, जिनकी आह और फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, जिनके आंखों के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। यह हमारी बदकिस्मती है।

मैं एक हिसाब आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमारे मुल्क की आबादी इस वक्त 80 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। यह बड़ी परेशानी की बात है। इसलिए खाना-पानी मंसूबाबंदी के ऊपर जोर देना चाहिए। यह लोगों को समझा बुझा कर किया जा सकता है कि उसके क्या नुकसानात हैं और आगे चलकर क्या हो सकता है। ये सारी बातें हैं, ये अपनी जगह ठीक हैं। मैं उसकी हिमायत करता हूं। लेकिन अनाज की कुल पैदावार हमारे मुल्क में कितनी होती है इसके लिए मैं यहां दो आंकड़े दे रहा हूं। 1950-51 में 5 करोड़ 8 लाख टन अनाज पैदा हुआ था पूरे देश में। अब 41-42 वर्ष बाद पैदा हो रहा है 17 करोड़ 62 लाख टन अनाज। अब 80 करोड़ लोगों को दो वक्त पेट भर खाना खिलाने के लिए कितने अनाज की जरूरत है। यह आंकड़े सरकारी हैं। हमने नहीं बनाए हैं। मैं बहुत मामूली तरीके से इस मामले को रखना चाहता हूं। कोई भी आदमी इसको समझ जायेगा। इसके लिए कोई ज्यादा पढ़ने-लिखने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को एक दिन में खाने के लिए आधा किलो अनाज काफी होता है, चावल, दाल, गेहूं मिलाकर। महीने में उसको 15 किलो अनाज चाहिए। अगर महीने में 15 किलो अनाज चाहिए तो साल में 180 किलो अनाज चाहिए यानी 180 किलो अनाज का मतलब है साढ़े 4 मन। एक आदमी को अगर साढ़े चार मन चाहिए साल भर के लिए तो दो आदमी के लिए 9 मन, चार आदमी के लिए 18 मन और 6 आदमी के लिए एक टन। एक टन अनाज अगर दे दिया जाए 6 आदमी साल भर पेट भर खाना खा सकता है। अगर एक करोड़ टन अनाज दे दिया जाए तो 6 करोड़ आदमियों का गुजारा होगा। अगर 10 करोड़ टन अनाज दे दिया जायेगा तो 60 करोड़ लोग खायेंगे। 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए साढ़े 12 करोड़ से 13 करोड़ टन काफी रहेगा। इस 80 करोड़ की आबादी में दो दिन के बच्चे से लेकर 60, 70, 80 साल के बूढ़े तक सब लोग हैं यह सब आधा के० जी० खाने वाले नहीं हैं। मैंने आसानी से समझाने के लिए यह सब हिसाब आपके सामने रखा है। तो 12-13 करोड़ टन अनाज होने से ही पूरी आबादी को खिलाया जा सकता है। यहां 70 लाख टन से भी ज्यादा अनाज पैदा होता है, लेकिन फिर भी चीजों के दाम कम नहीं होते हैं। आखिर यह अनाज जाता कहां है? सरकार विदेशों से गेहूं मंगा कर विदेशी मुद्रा खर्च करती है। यह किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है कि इसके अन्दर क्या खेल है। ट्रेड यूनियनों की तरफ से बहुत पहले एक मतालबा रखा गया था कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था में रह कर भी कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी सूरत यह है कि गेहूं, चावल, राशन, कोयला, दाल, नमक, शक्कर, साबुन और कपड़ा, ये जो जरूरत की जिन्दगी की लाजमी चीजें हैं, इन 14 चीजों की लिस्ट बना कर दी गई थी। यह बहुत दिन पहले की बात

है जब श्रीमति इन्दिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थीं । यह कहा गया कि आप इन 14 चीजों के कंट्रोल रेट मुकर्रर कर दीजिए और उस पर अमल दरामद के लिए सूरत यह होगी कि किसान अपने खेत में जो पैदावार करता है उसको मुनासिब दाम देकर, उसकी मेहनत और लागत से कुछ ज्यादा देकर सरकार उसको खरीदे और फिर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के जरिये उसको तकसीम किया जाये । इससे एक तो फायदा यह होगा कि अगर सरकार पांच लाख दुकानें खोलेगी तो 25 लाख लोगों को रोजी मिलेगी और दूसरा यह होगा कि एक कीमत पर गरीब तबके के लोगों को तमाम चीजें मिलेंगी । लोग सरकार को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देंगे कि सरकार ने कम से कम इतनी महंगाई की मार से बचाया । लेकिन उस पर सरकार ने कोई ध्यान नही दिया ।

एक मौके पर एक प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने बात की । मैंने उनको समझा कर कहा कि आप इतना तो कीजिए । उन्होंने कहा कि स्कीम तो अच्छी है, मगर इससे जो अनाज के व्यापारी हैं वे नाराज हो जाएंगे । मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार अमीरों को भी खुश रखे और गरीबों को भी खुश रखे, यह हो नहीं सकता । दुल्हा का भी भाई और दुल्हन का भी भाई, यह दुनिया में नहीं हो सकता । सरकार को तय करना होगा कि उसकी पालिसी किसको फायदा पहुंचाने की है और किस को नुकसान पहुंचाने की है । अगर सरकार गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो अमीरों को नुकसान होगा । आपको एक इरादा करके चलना होगा । ऐसी कोई पालिसी हो नहीं सकती है कि जिससे सबका भला हो जाए । हमारी मुसीबत यही है अंग्रेजों के जमाने में साम्राजी राज को मजबूत बनाने के लिए गरीबों को दबाया गया और जो जमींदारी और रैयतवाड़ी सिस्टम था उसमें नवाब, राजा और महाराजाओं को जन्म दिया गया जिन्होंने गांवों के गरीब लोगों का खून पीकर अंग्रेजों के राज को बनाए रखा । उस फ्यूड्ल सिस्टम को दफ़न करने के बजाय हमारे सियासी लीडरों ने उनसे समझौता कर लिया । जो लोग नवाब, राजा महाराजा थे वे आज राजनैतिक दलों के नेता बन गए हैं । तो यह कैसे होगा ? यह होने वाला नहीं है । इसलिए सरकार जितने भी वायदे चीजों के दाम कम करने के बारे में बात करती है वे वायदे ही रह जाते हैं । अब तो लोगों का विश्वास भी उस पर से खत्म हो गया है और इसलिए लोग मैदान में उतर आए हैं । मोहतरमा आपने देखा होगा, पिछले साल किस तरह से नवम्बर के महीने में 29 तारीख को पूरे हिन्दुस्तान के कल–कारखानों के मजदूरों ने जनरल स्ट्राइक की थी । इस साल 16 जून को जनरल स्ट्राइक हुई थी जिसमें डेढ़ करोड़ मजदूरों ने भाग लिया था । नवम्बर 25 तारीख को दिल्ली के बोट क्लब पर हिन्दुस्तान के कोने–कोने से लोग आए थे । किसी अखबार ने 5 लाख बताया, किसी ने 10 लाख बताया और किसी ने 8 लाख बताया । यह कहना तो मुश्किल है कि कितने लोग थे, लेकिन यह बात कही जा सकती है कि इतनी बड़ी तादाद में मजदूर कभी भी राजधानी में देखे नहीं गए थे । यह सरकार के लिए एक वारनिंग है कि वह अपनी पालिसी पर नजरसानी करे, वरना लोग इस को चलने नहीं देंगे । सरकार के लिए मुश्किल

श्री मोहम्मद अमीन

क्या है कि विदेशी कर्जे में वह डूबी हुई है। विदेशों से कर्ज मांग मांग कर अगर देश को चलाना है तो यह कोई समझदारी की बात नहीं है और इज्जते नफ्स का भी सवाल आता है। हम तो यह कहते हैं कि जो कुछ आपको अपने देश में मिलता है, उसकी बुनियाद पर खड़े होकर अपनी पालिसी बनाइए। सरकार ईमानदारी के साथ यह साबित कर दे कि वह गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाना चाहती है तो लोग और कुर्बानियां देंगे। हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है जहां के लोग थोड़े में गुजारा करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं ज्यादा का लालच उनको नहीं होता। मगर तकलीफ तब होती है जब वह भी नहीं मिलता। मगर सरकार चल रही है, विदेशों से कर्जा मांगती है लोगों पर टैक्स लगाती है और नोट छापती है। यह तीन काम करती है। आज से नहीं, 1947 से। अब यह बढ गया है। पहले इतना ज्यादा नहीं था। विदेशों से कर्ज लेना भी बुरी बात है नोट। छापना भी गलत बात है और लोगों पर टैक्स लगाना भी बुरी बात है। इससे तमाम चीजों के दाम बढ गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले पेट्रोल और डीजल के ऊपर दाम बढ़ गए। सरकार खुद ही अगर दाम बढ़ाए तो फिर कम कैसे होगा, कम होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मोहतरमा, हमारे देश के लोगों ने सरकार को वार्निंग दे दी है और यह कहा है कि वर्ल्ड बैंक की बात पर मत चलिए। वर्ल्ड बैंक और इन्टरनेशनल मानेटरी फण्ड ये महाजन हैं और महाजनों का जो चरित्र होता है वह सबको मालूम है। उनसे आप कर्जा मांगने जायेंगे तो कर्जा वह आपको देंगे मगर उसके साथ वह अपनी शर्तें भी देंगे। ये वर्ल्ड बैंक के लोग क्या-क्या शर्तें देते हैं? आपको याद होगा कि इसी सदन में हम लोगों ने कितनी ही बार यह मतालबा प्राइम मिनिस्टर से किया कि वर्ल्ड बैंक के साथ आपकी क्या बात हुई है, हम लोगों को बतलाइए, पार्लियामेंट को बतलाइए। लेकिन कभी नहीं बताया, न प्राइम मिनिस्टर ने बताया और न फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की क्या मर्यादा रह गई है कि जब इण्डियन एक्सप्रेस में कोई खत छप जाता है तब बात सामने आती है, तभी शोर मचता है। महाजन जब कर्जा देता है तो वह कहता है कि कर्जा ले जाइए मगर पैसा कहां खर्च करेंगे, वह हम तय करेंगे और इसको मान करके, सर झुकाकर यह लोग चले आते हैं। वे कहते हैं कि यह रुपया ले जाइए और इस-से यहां की बनी हुई टेरीकाट की साड़ियां खरीदकर हिन्दुस्तानी औरतों को पहनाइए तो हमारे कपड़े की सनअत तबाह नहीं होगी? वह कहते हैं कि खाद के ऊपर सब्सिडी उठाओ, जो उठा दी जाती है तो क्या खाद के दाम बढ़ेंगे नहीं? वह कहते हैं कि ऐसी पालिसी अख्तियार करो ताकि मजदूरों की छटनी हो ताकि लोग बेकार हो जायें। वह कहते हैं कि हमारा रुपया लेना है तो यह करना पड़ेगा। वह कहते हैं कि सरकारी कारखाने जो नुकसान में चल रहे हैं उनको प्राइवेट वालों के हवाले कर दो। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास इस वक्त कुल मिलाकर के 134 उद्योग हैं। इसमें खुद सरकारी हिसाब से 98 उद्योगों में नुकसान होता है और 36 में आज भी मुनाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। उसमें, जहां तक मुझे याद है कि इन 36 उद्योगों में जो मुनाफा होता है वह 98 के नुकसान को करीब-करीब पूरा कर देता है। लेकिन सरकार एक तरफ से बी० आई० एफ० आर०

में भेज रही है मामलात को। अब यह जो आपका मोटर का कारखाना था, मारूति, यह नफे में चल रहा था। मोहतरमा, यह आप भी जानती हैं। तो इसको क्यों प्राइवेटाइज्ड किया ? इसमें तो नुकसान नहीं होता था । यह वर्ल्ड बैंक का करिश्मा है, वर्ल्ड बैंक का खेल है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब समाप्त करिए । समय हो चुका है ।

श्री मोहम्मद अमीन : मैं तो रेलेवेन्ट बातें कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष : (श्रीमती सुषमा स्वराज) रेलेवेन्ट बातें कह रहे हैं लेकिन समाप्ति की तरफ बढ़िये ।

श्री मोहम्मद अमीन : मुझे 5–7 मिनट और दे दीजिए ।

अब यह प्राइवेटाइज्ड का जो झगड़ा चल गया है, अखबार वाले भी शोर मचा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन । क्या उनसे यह पूछा जा सकता है कि जो 3 लाख कल–कारखाने बंद हैं पूरे हिन्दुस्तान में वे सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं । अगर प्राइवेट सेक्टर इतना ही काबिले तारीफ है तो इतने कारखाने बन्द क्यों हैं ? असल बात वह नहीं है। असल बात यह है कि सरकार की पालिसी गलत है और उनके इरादे ठीक नहीं है । हमारे यहां फौलाद के जो कारखाने हैं उनकी जो इंस्टाल्ड केपेसिटी है उससे बहुत कम पैदावार हो रही है और सरकार विदेशों से फौलाद मंगवाती है, विदेशी मुद्रा खर्च करती है । पेपर इण्डस्ट्री को आप देखें। हिन्दुस्तान में 50 कारखाने हैं, जिसमें 25 कारखाने बन्द हैं । बन्द इसलिए नहीं हैं कि उसके लिए बाजार नहीं है। कागज का बाजार बहुत अच्छा है लेकिन रा–मेटिरियल की कमी हो गई है । रा–मेटिरियल का इंतजाम न करके कारखानों को बन्द कर दिया गया, मजदूरों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया है और मांग को पूरा करने के लिए सरकार विदेशों से कागज मंगा रही है। इसी तरह से पटसन इंडस्ट्री है । सिंथेटिक्स को अंधाधुंध लाइसेंस दे दिए गए यू० पी० में, दिल्ली में, हरियाणा में और न जाने कहां–कहां । सिन्थेटिक पेकेजिंग मेटिरियल सस्ता पड़ता है लेकिन इससे जूट की सनअत बरबाद हो रही है। बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि पश्चिमी बंगाल में बाएं बाजू की हकूमत है वह मुसीबत में पड़े तो पड़े लेकिन हम यह कहते हैं कि जूट की सनअत में काम करने वाले 50 फ़ीसदी लोग गैर बंगाली हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के हैं । यह सारे लोग परेशान हैं । कोई यह पूछ सकता है कि अपनी सनअत को बरबाद करने के रास्ते पर कोई सरकार जा सकती है जिसको अपने देश से, अपने लोगों से और अपने मजदूरों से मोहब्बत हो। इस तरह से आवे का आवा ही उल्टा है। हम लोगों की पश्चिमी बंगाल के पार्लियामेंट के मैम्बरों की एक मीटिंग

श्री मोहम्मद अमीन

चार पांच महीने पहले लेबर मिनिस्टर के साथ हुई थी। मंत्री जी ने यह कहा कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हमने उनसे कहा था कि आपके 134 सरकारी कारखाने हैं। आप यह कहते हैं कि उनमें से 98 में नुक्सान हो रहा है, इसलिए आप एक-एक कारखाने को लेकर के बैठिए। हमारी जितनी भी यूनियंस हैं, उनको भी बुलाइये क्योंकि यूनियंस की बात आप लोग सुनते नहीं हैं। ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और ब्यूराक्रेट्स के अपने तौर-तरीके होते हैं, अपने मफ़ादात होते हैं, उन्होंने अपना चक्कर फैलाया हुआ है। इसलिए नुक्सान होता है। आज तीन लाख कारखाने बन्द हैं। उनके बारे में रिजर्व बैंक ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मजदूरों की वजह से सिर्फ़ दो फ़ीसदी कारखाने बन्द हैं। 98 फ़ीसदी कारखाने इसलिए बन्द हैं कि कहीं रा-मेटिरियल नहीं है, कहीं फाइनेंस नहीं है और कहीं बाजार नहीं है, मिसमेनेजमेंट है और करप्शन है। यह हालत है। इसलिए अगर यूनियंस के साथ बैठा जाए तो मजदूर अपनी रोजी का ख्याल रखता है। वह सारी सच्ची बात आपको बता देंगे। अगर उनकी बातों की रोशिनी में इकदामात किए जाएं तो जो कारखाने आज नुक्सान में चल रहे हैं, वह कल नफे में चल सकेंगे। यह होना चाहिए तभी कीमतें कम की जा सकती हैं। दो सवाल हैं जो इस वक्त हिन्दुस्तान के लोगों को तबाह कर रहे हैं, एक है मंहगाई और दूसरा है बेरोजगारी। इन दोनों का गहरा ताल्लुक है बेसिक लैंड रिफ़ार्म्स से। अगर बेसिक लैंड रिफ़ार्म्स हो जाएं, जमीन किसानों को मिल जाए तो किसानों की कुव्वतेखरीद बढ़ेगी और कारखानों का जितना माल है सबका सब बिक जाएगा और हजारों नए कारखाने आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी इससे बेकार लोगों को काम मिलेगा। बेसिक लैण्ड रिफ़ार्म्स के बगैर न तो बेरोजगारी का मसला हल हो सकता है और न मंहगाई कम हो सकती है। अगर कोई सरकार इस बात का दावा करे कि मंहगाई कम कर देंगे तो यह गलत होगा और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी और इसमें कभी सफ़लता नहीं मिलेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं यह रेजोल्यूशन सदन के सामने रखता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इसको मंजूर किया जाए।

شری محمّد امین: محترمہ۔ اب مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ۔

لگی ہے آگ کچھ اس طرح سارے گلشن میں
کہ کوئی آشیاں محفوظ نہ رہ پائے

محترمہ۔ ایسے تو جب سے دیش آزاد ہوا تب سے مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے لیکن شروع میں ایسا ہوا تھا کہ سال چھ مہینے میں کبھی کسی چیز کا دام بڑھ جاتا تھا۔ اور اب یہ حال ہے کہ ہر مہینہ۔ کبھی کبھی ہر ہفتہ اور کبھی کبھی ہر روز کچھ نہ کچھ چیزوں کا دام بڑھ جاتا ہے سرکار کبھی کبھی دعویٰ کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے دام گھٹا دیئے۔ ابھی فائنانس منسٹر صاحب نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ

انفلیشن ڈبل ڈجٹ سے نیچے کر دیا ہے
اور اب سنگل ڈجٹ پر لا رہے ہیں۔ اصل
میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اکتوبر۔ نومبر
مہینہ میں جب کھیتوں میں پیداوار
ہوتی ہے نئی سبزی ترکاری آتی ہے۔
اناج آتا ہے تو دام تھوڑا سا کم ہوتا ہے
آلو پیاز۔ ٹماٹر اور دوسری سبزیوں
کا اگر تھوڑا سا دام اتر جاتا ہے تو سرکار
اپنے ہاتھ سے اپنی پیٹھ ٹھوکنے لگتی ہے
کہ دیکھئے دام کم ہو گیا مگر اس کے دو
مہینے بعد ہی دام پھر چڑھ جاتا ہے۔
اور پچھلے سال کے حساب سے اگلے سال
اس کی سطح کافی اونچی ہو جاتی ہے۔ یہی
تماشہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں بہت
زیادہ حساب کتاب کے جال میں پھنسنا
نہیں چاہتا۔ کیوں کہ جو لوگ حساب
کتاب بناتے ہیں۔ ان کی کیا بنیاد ہوتی
ہے۔ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں
آتی۔ اس لئے سرکاری میڈیا کے اوپر
سے عوام کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے کیونکہ
ان کا جو اپنا زندگی کا تجربہ ہے یہ انکو
بتاتا ہے کہ دام گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا
ہے۔ اس لئے اخبار چاہے کچھ بھی لکھے
ٹیلی ویژن پر کچھ بھی پرچار کیا جائے یا
گورنمنٹ کچھ بھی کہے وہ بات لوگوں
کے دلوں میں نہیں اترتی ہے مگر اس
کے باوجود میں دو چیزیں پیش کرنا چاہتا
ہوں۔ ایک چارٹ چھپا تھا۔ ۲۶ نومبر
کو ہندو اخبار میں۔ اس میں مارچ ۱۹۹۱ء
سے لیکر اکتوبر ۱۹۹۲ء کا ماہوار گوشوارہ ہے
میں سب نہیں پڑھتا۔ صرف مارچ ۱۹۹۱ء
میں کیا پوزیشن تھی اور اکتوبر ۱۹۹۲ء میں
کیا پوزیشن ہے۔ یہی دو فگر بتاتا ہوں۔

پرائمری آرٹیکل

مارچ ۱۹۹۱ء میں ۱۹۵ اعشاریہ
۶ اور اکتوبر ۱۹۹۲ میں ۲۳۷ اعشاریہ ۱
یعنی کل بڑھا ہے۔ ۴۱ اعشاریہ ۵ پرسینٹ۔

فیول گروپ:

مارچ ۱۹۹۱ میں ۱۸۸ اعشاریہ ۶
اور اکتوبر ۱۹۹۲ء ۲۳۴ اعشاریہ ۹ یعنی کل
بڑھا ہے ۴۶ اعشاریہ ۳ پرسینٹ۔

مینوفیکچرڈ پروڈکٹس

مارچ ۱۹۹۱ میں ۱۹۰ اعشاریہ ۱ اور
اکتوبر ۱۹۹۲ میں ۲۲۶ اعشاریہ ۳ یعنی
کل بڑھا ہے ۳۶ اعشاریہ ۲ پرسینٹ۔

آل کموڈٹیز

مارچ ۱۹۹۱ میں ۱۹۱ اعشاریہ ۷
اور اکتوبر ۱۹۹۲ میں ۲۳۰ اعشاریہ ۷۔
یعنی کہ ۳۹ اعشاریہ ۷ پرسینٹ کا اضافہ
ہوا ہے۔

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[SHRI MOHD. AMIN]

اگر پرسینٹیج نکالا جائے تو دیکھا جائے گا کہ ایک سال کے اندر تقریباً ۲۵-۲۴ پرسینٹ دام بڑھے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار جب بنی اور جس کو بنے ہوئے ایک سال پانچ مہینے ہو گئے ہیں اتنے ہی دنوں میں کل ملا کر چیزوں کے دام ۲۴ سے ۲۵ پرسینٹ بڑھ گئے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورت حال ہے۔ کیوں کہ اس اعتبار سے سرکار ملازمین یا مزدور یا ملازمت پیشہ لوگوں کے مہنگائی بھتے میں اس حساب سے کوئی اضافہ نہیں ہوا اور جو لوگ بیکار ہیں ان کا تو سوائے خدا کے کوئی مددگار نہیں ہے۔ مہنگائی کی جو مار ان کے اوپر پڑتی ہے اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے ان کروڑوں لوگوں کو جو بازار کا دام بڑھا کر لوٹتے ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔

1991 میں لوک سبھا کا جو چناؤ ہوا تھا۔ اس چناؤ کے الیکشن مینی فیسٹو میں کانگریس پارٹی نے تحریری طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ملک کے عوام اگر انہیں حکومت سونپ دیں تو وہ سو دنوں کے اندر مہنگائی کو نیچے اتار دیں گے۔ یہ چھپا ہے اس میں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب ان کی حکومت بن گئی اور منموہن سنگھ جی فائنانس منسٹر ہوئے تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ہونے والا نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کا ملک کے عوام پر۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پر سیاسی پارٹیوں کے وعدوں پر کتنا بھروسہ رہ جائے گا۔

اخباروں نے اس کے بعد کمینٹ کیا کہ یہ لوگ جو چناؤ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ تو کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مہنگائی کم کرنے کے اوپر ان کا دھیان کم رہتا ہے۔ وہ کروڑوں روپیہ جو خرچ ہوا ہے وہ واپس کیسے آئے گا۔ اس طرف ان کا دھیان زیادہ رہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اخباروں میں نکلتی ہیں اور اس سے میرے خیال میں سرکار کی کریڈیبلیٹی کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔

دوسرا ایک اداہرن میں اور دے رہا ہوں۔ وہ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کا۔ ایک تو میں نے آپ کو ہول سیل پرائس انڈیکس بتایا ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کا حساب جو سرکار کا ہے۔ اس میں میں جون اور سے اکتوبر ۹۲ تک کا حساب دے رہا ہوں

جون ۹۱ میں یہ تھا ۲۰۹۔ جولائی میں ہوا ۲۱۴۔ اگست میں ۲۱۷۔ ستمبر میں ۲۲۱ اکتوبر میں ۲۲۳۔ نومبر میں ۲۲۵۔ دسمبر میں ۲۲۵۔ جنوری ۹۲ میں ۲۲۸۔ فروری میں ۲۲۹۔ مارچ میں ۲۲۹۔ اپریل میں ۲۳۱۔ مئی میں ۲۳۴۔ جون میں ۲۳۶۔ جولائی میں ۲۴۲، اگست میں ۲۴۲۔ ستمبر میں ۲۴۳۔ اکتوبر میں ۲۴۴۔ یعنی اس طرح ۲۰۹ سے ۲۴۴ پر جاکر یہ پہنچ گیا۔ ان دونوں حساب سے ثابت ہو جاتا ہے کہ چیزوں کے دام کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ آج کا یہ اخبار ہے "آبزرور" اس نے اپنے صفحہ ۷ پر دیکھئے کیا تماشہ کیا ہے پرائس انڈیکس فال ہوا ہے۔

اب اس میں اگر ایکچوئل لیبر کا حساب ایک قسم کا لیا ہے اور ورکرس کنزیومرس پرائس انڈیکس کا ایک قسم کا۔ اور اس کے بعد یہ مان لیا ہے کہ کنزیومرس پرائس انڈیکس بھی بڑھا ہے اور روپیہ کا دام بھی گھٹ گیا ہے۔ سرکار کی پرائس پالیسی۔ قیمتوں کی پالیسی کیا ہے یہ ابھی تک عوام کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی پالیسی ہے بھی یا نہیں اس لئے کہ ہمارے دیش کی جو حالت ہے۔ یہاں کی مٹی اتنی زرخیز ہے یہاں پانی جس پرکار مقدار میں پایا جاتا ہے، موسمی حالات۔ قدرت مہربان ہے۔ جاڑا گرمی اور برسات کی وجہ سے اتنا عمدہ موسم دنیا کے بہت کم ملکوں میں ہوگا اور لوگ بھی محنتی ہیں۔ سرکار کی طرف سے جو کم سے کم انتظام کیا جانا چاہیئے وہ اگر ہو تو کسی چیز کی یہاں کمی نہیں ہو سکتی۔

یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیئے کہ ۱۹۰ برس تک انگریز سامراجیہ وادیوں کی غلامی کے بعد دیش آزاد ہوا۔ آزادی جس راستے پر آئی اور جس طرح انہوں نے ملک کا بٹوارا کر دیا دھرم کے نام پر۔ مذہب کے نام پر۔ یہ تو اپنی جگہ افسوسناک بات ہے اس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی مگر یہاں وہ بے انصافی ہو گئی ہے۔ مگر اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہیئے تھا پاکستان اور بنگلہ دیش میں کیا حال ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ وہ ہماری بحث کی چیز نہیں ہے لیکن ہندوستان میں پہلا کام جو کرنا چاہیئے تھا وہ تھا بیک لینڈ ریفارمس۔ بنیادی اصلاحات آراضلات جس کا وعدہ بھی کانگریس کے لیڈروں نے کیا تھا۔

آزادی کے پہلے کانگریس کا کوئی ادھیویشن ایسا نہیں ملے گا جس میں اس سوال پر رزولیوشن پاس نہ کیا گیا ہو کہ ملک آزاد ہوگا تو زمینداری کا خاتمہ کر کے

[SHRI MOHD. AMIN.]

تمام زمین کسانوں کو بانٹ دیں گے لیکن آزادی آنے کے اتنے دنوں میں کیا وہ بیسک لینڈ ریفورم ہوئے۔ قانون ضرور بنے۔ مختلف ریاستوں میں مختلف قانون بنے تھے لیکن ان قانون میں بہت ساری خامیاں بھر دی گئیں تھیں۔ زمینداروں کے لئے جو کسانوں کو زمین نہیں دلانا چاہتے تھے عدالتوں میں جانے کا راستہ کھول دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیسک لینڈ ریفارم ہو نہیں پائے جو کچھ ہوا کسانوں پہلے ہی کمزور تھا۔ کچھ نہیں کر پایا پھر بھی کچھ آندھرا پردیش میں ہوا۔ جہاں تیلنگانا کی انقلابی تحریک چلی تھی۔ جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنے جیون کی قربانی دی تھی۔ نظام کے راج میں اور زمینوں پر قبضہ کیا تھا۔ پھر وہ زمین فوجی کارروائی کے بعد ان سے چھین لی گئی۔ کچھ رکھ پائے کچھ چھین گئی۔ کافی کچھ ہوا۔ ابھی ریزرو بینک اور بھارت سرکار کا حساب یہ بتاتا ہے کہ سارے ہندوستان میں جتنی زمینوں کا بٹوارا ہوا اس کا ۲۲ فیصدی ہوا ہے۔ مغربی بنگال میں ایک ریاست ہیں۔ اس لئے کہ مغربی بنگال میں بائیں محاذ کی حکومت ہے وہ اپنے محدود اختیارات کے اندر اپنے ایک اصول پر چلتی ہے۔

اس میں کھیت مزدوروں۔ بٹائی داروں اور غریب کسانوں نے۔ اس کا ساتھ دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہاں پر متحدہ محاذ کی حکومت بنی تھی میں بھی وہاں منسٹر تھا۔ اس وقت سرکار نے یہ کہا کہ کسانوں سے اگر آپ انتظار میں بیٹھے رہے کہ سرکار آپ کو زمین دے دیگی تو آپ کو زمین نہیں ملے گی آپ جانتے ہیں سرکار کو تو قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے لیکن حد بندی کے اوپر جو بھی زمین ہے جو ناجائز طریقے سے چھپا کر رکھی گئی ہے اس پر کسان سنگٹھت ہو کر اگر قبضہ کریں تو ہم آپ کی یہ مدد ضرور کر سکتے ہیں کہ زمیندار جب عدالت میں جائیں گے تو پہلے جیسے پولیس اس کی مدد کرتی تھی ہم پولیس کو اس کی مدد کرنے سے روک دیں گے۔ آگے کا معاملہ آپ لوگ کو جیتنا پڑیگا۔ اتنا سہارا مل گیا تو گاؤں گاؤں میں کسانوں کی تحریک کھڑی ہو گئی اور لوگوں کو معلوم تھا کہ پانچ ہزار دس ہزار بیگھے زمین دبا کر وہ بیٹھے تھے۔ اس طرح سے پشچمی بنگال میں زمین کا بٹوارا ہوا۔

محترمہ۔ چار بار بائیں محاذ کی حکومت پشچمی بنگال میں بنی سرمایہ دارانہ نظام میں رہتے ہوئے بھی کمیونسٹوں کو تجارت مل گئی ساری دنیا کے لوگ تعجب

کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا۔ لوگ کیسے جیت جاتے ہیں بعض لوگ تو الزام یہ لگاتے ہیں کہ پشچمی بنگال میں الیکشن ٹھیک سے ہوتے نہیں ہیں۔ اس لئے یہ لوگ جیت جاتے ہیں لیکن خود الیکشن کمیشن سرٹیفکیٹ دے چکا ہے کہ پشچمی بنگال میں الیکشن میں منصفانہ اور پرامن ہوتے ہیں۔ سارے ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی تو وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اس سرکار نے کیا ایسا کیا ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چودہ برس میں سولہ الیکشن ہو چکے ہیں۔ چار مرتبہ لوک سبھا کے۔ چار دفعہ پنچایتوں کے چار دفعہ میونسپلٹیوں اور کارپوریشن کے اور ان سولہ الیکشنوں میں ہی بائیں محاذ کے امیدوار سپھل ہوئے اس لئے کہ انہوں نے گاؤں میں کسانوں کا ساتھ دیا اور کل کارخانوں میں مزدوروں کی تحریک کی حمایت کی۔ سرکاری کرمچاری جب اپنی مانگوں کی حمایت کے لئے لڑتے ہیں تو ان کی حمایت کی اس لئے جو زمین کسانوں کو ملنے کی آج تو اناج سستا ہے اگر آپ پشچمی بنگال اور کلکتہ میں تشریف لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کے کسی بھی شہر سے بنگال میں کچھ چیزیں سستی ہیں۔ سرکار کے ہاتھ میں تو پورے ملک کے نام کنٹرول کرنے کے اختیار ہے نہیں۔ نہ تو مالی اختیار ہے نہ قانونی جو محدود اختیار ہیں انہیں کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی ہندوستان میں جہاں کئی ریاستوں میں غیر کانگریسی حکومتیں ہیں اور کئی ریاستوں میں کانگریسی حکومتیں ہیں۔ ان کی بھی لینڈ ریفورم کرنے سے کسی نے روکا۔ وی۔ پی۔ سنگھ کی حکومت نے ایک بڑا اچھا کام کیا لینڈ ریفارم کے متعلق۔ جتنے قوانین بنے ہوئے ہیں سارے ملک میں انہوں نے دستور میں ترمیم کر کے ان تمام قوانین کو دستور کی نویں شیڈولڈ کے تحت لا دیا اسی سدن میں ہم لوگوں نے پاس کیا تھا تاکہ اس کے خلاف عدالت میں جانے کا راستہ بند ہو جائے۔ اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن یہ کام وی۔ پی۔ سنگھ حکومت نے بڑی ایمانداری سے کیا تھا۔ اس کے نقش قدم پر چل کر اگر اس قدم کو آگے بڑھایا جاتا تو بھی بات بن سکتی تھی۔ لیکن یہاں تو کبھی بوفورس کا معاملہ چل پڑتا ہے کبھی اسکیم چل پڑتا ہے اور کبھی مندر مسجد چل پڑتا ہے۔ لوگ اس میں پھنس جاتے

[SHRI MOHD. AMIN.]

ہیں۔ کروڑوں لوگوں کو دو وقت دال روٹی نہیں ملتی تن ڈھکنے کے لئے کپڑا نہیں ملتا۔ اس طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ محترمہ۔ گاؤں میں دیہات میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ سردی میں لوگ ٹھٹھر کر مر جاتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لو لگ جاتی ہے۔ اخباروں میں نکلتا ہے کہ لو لگنے سے کتنے لوگ مرے۔ جب برسات کا موسم آتا ہے۔ جب سیلاب آتا ہے تو گاؤں کا گاؤں بہا کر لے جاتا ہے غریب لوگوں کو کسی بھی موسم میں چین نہیں ہے۔ یہ سارے مرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ انتہائی غریب ہیں اور پاورٹی لین کے نیچے رہ کر زندگی گزارنے کے لئے مجبور ہیں۔ جن کی آہ اور فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جن کی آنکھوں کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔

میں ایک حساب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کی آبادی اس وقت ۸۰ کروڑ سے اوپر جا چکی ہے۔ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے اسی لئے خاندانی منصوبہ بندی کے اوپر زور دینا چاہیئے یہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے کیا جا سکتا ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ میں اس کی حمایت کرتا ہوں لیکن اناج کی کل پیداوار ہمارے ملک میں کتنی ہوتی ہے۔ اس کے لئے میں یہاں دو آنکڑے دے رہا ہوں۔ ۱۹۵۰-۵۱ء میں ۵ کروڑ آٹھ لاکھ ٹن اناج پیدا ہوا تھا پورے دیش میں اب ۴۱-۴۲ ورش بعد پیدا ہو رہا ہے ۱۷ کروڑ ۶۲ لاکھ ٹن اناج۔ اب ۸۰ کروڑ لوگوں کو دو وقت پیٹ بھر کھانا کھلانے کے لئے کتنے اناج کی ضرورت ہے۔ یہ آنکڑے سرکاری ہیں ہم نے نہیں بنائے ہیں۔ میں بہت معمولی طریقہ سے اس معاملہ کو رکھنا چاہتا ہوں کوئی بھی آدمی اس کو سمجھ جائے گا۔ اس کے لئے کوئی زیادہ لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ایک دن میں کھانے کیلئے آدھ کلو اناج کافی ہوتا ہے۔ چاول۔ دال گیہوں ملا کر۔ مہینہ میں اس کو ۱۵ کلو اناج چاہیئے۔ اگر مہینہ میں ۱۵ کلو اناج چاہیئے تو سال میں ایک سو اسّی کلو اناج چاہیئے یعنی ۱۸۰ کلو اناج کا مطلب ہے ساڑھے چار من ایک آدمی کو اگر ساڑھے چار من چاہیئے سال بھر کے لئے ۹ من ہم آدمیوں کے لئے اور ۶ آدمیوں کے لئے ایک ٹن۔ ایک ٹن

لسٹ بنا کر دی گئی تھی۔ یہ بہت دن پہلے کی بات ہے جب شریمتی اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھیں۔ یہ کہا گیا کہ آپ ان اہم چیزوں کے کنٹرول ریٹ مقرر کر دیجئے اور اس پر عمل درآمد کے لئے صورت یہ ہوگی کہ کسان اپنے کھیت میں جو پیداوار کرتا ہے اس کو مناسب دام دے کر اس کی محنت اور لاگت سے کچھ زیادہ دے کر سرکار اس کو خریدے اور پھر پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم کے لئے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سرکار ۵ لاکھ دکانیں کھولے گی تو ۲۵ لاکھ لوگوں کو روزی ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ ایک قیمت غریب طبقہ کے لوگوں کو تمام چیزیں ملیں گی۔ لوگ سرکار کو دونوں ہاتھ اُٹھا کر آشیرواد دیں گے کہ سرکار نے کم سے کم اتنی مہنگائی کی مار سے بچایا۔ لیکن سرکار نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔

ایک موقع پر ایک پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی۔ میں نے ان کو سمجھا کر کہا کہ آپ اتنا تو کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اسکیم تو اچھی ہے مگر اس سے اناج کے جو بیوپاری ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔

اناج اگر دے دیا جائے تو جیسے آدمی سال بھر کھا سکتے ہیں۔ اگر ایک کروڑ ٹن اناج دے دیا جائے تو جیسے کروڑ آدمیوں کا گذارا ہوگا اگر دس کروڑ ٹن اناج دے دیا جائے گا تو ۶۰ کروڑ لوگ کھائیں گے۔ ۸۰ کروڑ لوگوں کی آبادی میں دو دن کے بچے سے لے کر ساٹھ ستر اسی سال کے بوڑھے تک سب لوگ ہیں یہ سب آدھا کھے۔ جی کھانا کھانے والے نہیں ہیں۔ میں نے آسانی سے سمجھانے کے لئے یہ سب حساب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ۱۳-۱۲ کروڑ ٹن اناج ہونے سے ہی پوری آبادی کو کھلایا جا سکتا ہے یہاں ۷۰ لاکھ ٹن سے بھی زیادہ اناج پیدا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چیزوں کے دام کم نہیں ہوتے ہیں۔ آخر یہ اناج جاتا کہاں ہے۔ سرکار ودیشیوں سے گیہوں مانگ کر ودیشی مدرا خرچ کرتی ہے۔ یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کھیل ہے۔ ٹریڈ یونینوں کی طرف سے بہت پہلے ایک مطالبہ رکھا گیا تھا کہ پونجی وادی سماج و یوستھا میں رہ کر بھی قیمتوں میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ گیہوں۔ چاول۔ راشن۔ کوئلہ۔ دال نمک۔ شکر۔ صابن اور کپڑا یہ جو ضروریات زندگی کی لازمی چیزیں ہیں ان اہم چیزوں کی

[SHRI MOHD. AMIN.]

میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سرکار امیروں کو بھی خوش رکھے اور غریبوں کو بھی خوش رکھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دلہا کا بھی بھائی اور دلہن کا بھی بھائی یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ سرکار کو طے کرنا ہوگا کہ اس کی پالیسی کس کو فائدہ پہنچانے کی اور کس کو نقصان پہنچانے کی ہے۔ اگر سرکار غریب لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو امیروں کو نقصان ہوگا۔ آپ کو ایک ارادہ کر کے چلنا ہوگا ایسی کوئی بھی پالیسی ہو نہیں سکتی ہے کہ جس سے سب کا بھلا ہو جائے۔ ہماری مصیبت یہی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں سامراجی راج کو مضبوط بنانے کے لئے غریبوں کو دبایا گیا اور جو زمین داری اور رعیت واڑی سسٹم تھا اس نے نواب۔ راجہ اور مہاراجاؤں کو جنم دیا۔ جنہوں نے گاؤں کے غریب لوگوں کا خون پی کر انگریزوں کے راج کو بنائے رکھا۔ اس فیوڈل سسٹم کو دفن کرنے کے بجائے ہمارے سیاسی لیڈروں نے ان سے سمجھوتہ کر لیا جو لوگ نواب راجہ اور مہاراجہ تھے۔ وہ ہی آج راج نیتک دلوں کے نیتا بن گئے ہیں تو یہ کیسے ہوگا۔ یہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے سرکار جتنے بھی وعدہ چیزوں کے دام کم کرنے کے بارے میں کرتی ہے وہ وعدہ ہی رہ جاتی ہیں۔ اب تو لوگوں کا وشواس بھی اس پر سے ختم ہو گیا ہے اور اس لئے لوگ میدان میں اتر آئے ہیں۔ محترمہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال کس طرح سے نومبر کے مہینے میں ۲۹ تاریخ کو پورے ہندوستان کے کل کارخانوں کے مزدوروں نے جنرل اسٹرائک کی تھی۔ اس سال ۱۶ جون کو جنرل اسٹرائک ہوئی تھی جس میں ڈیڑھ کروڑ مزدوروں نے بھاگ لیا تھا۔ نومبر ۲۵ تاریخ کو دلی کے بوٹ کلب پر ہندوستان کے کونے کونے سے کئی لاکھ لوگ آئے تھے۔ کسی اخبار نے ۵ لاکھ بتایا کسی نے ۱۰ لاکھ بتایا اور کسی نے ۸ لاکھ بتایا۔ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ کتنے لوگ تھے لیکن یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مزدور کبھی بھی راجدھانی میں دیکھے نہیں گئے تھے۔ یہ سرکار کے لئے ایک وارننگ ہے کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ ورنہ لوگ اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ سرکار کے لئے مشکل کیا ہے کہ ودیشی قرضے میں وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ ودیشوں سے مانگ کر اگر دیش کو چلانا ہے تو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے اور عزت نفس کا بھی سوال آتا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو اپنے دیش میں ملتا ہے اس کی بنیاد پر کھڑے ہو کر اپنی پالیسی بنائیے۔ سرکار ایمانداری کے

ساتھ اگر یہ ثابت کرے کہ وہ غریب طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے تو لوگ اور قربانیاں دیں گے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کے لوگ تھوڑے میں گزارا کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زیادہ کا لالچ ان کو نہیں ہوتا۔ مگر تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ بھی نہیں ملتا۔ مگر سرکار چل رہی ہے۔ ودیش سے قرضہ مانگتی ہے لوگوں پر ٹیکس لگاتی ہے اور نوٹ چھاپتی ہے۔ یہ تین کام وہ کرتی ہے آج سے نہیں ۱۹۴۷ سے اب یہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ودیشوں سے قرض لینا بھی بری بات ہے نوٹ چھاپنا بھی غلط بات ہے اور لوگوں پر ٹیکس لگانا بھی بری بات ہے۔ اس سے تمام چیزوں کے دام بڑھ گئے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پٹرول اور ڈیزل کے اوپر دام بڑھ گئے سرکار خود ہی اگر دام بڑھائے تو پھر کم کیسے ہوگا۔ کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اس لئے محترمہ ہمارے دیش کے لوگوں نے سرکار کو وارننگ دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ورلڈ بینک کی بات پر مت چلئے۔ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یہ مہاجن ہیں اور مہاجنوں کا جو چرتر ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے ان سے آپ قرضہ مانگنے جائیں گے تو قرضہ وہ آپ کو دیں گے۔ مگر اس کے ساتھ وہ اپنی شرطیں بھی دے دیں گے یہ ورلڈ بینک کے لوگ کیا کیا شرطیں دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسی سدن میں ہم لوگوں نے کتنی ہی بار یہ مطالبہ پرائم منسٹر سے کیا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے ہم لوگوں کو بتلائیے۔ پارلیمنٹ کو بتلائیے لیکن کبھی نہیں بتایا۔ پرائم منسٹر نے بتایا اور نہ فائننس منسٹر نے بتایا۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی کیا مریادا رہ گئی ہے کہ جب انڈین ایکسپریس میں کوئی خط چھپ جاتا ہے تب بات سامنے آتی ہے۔ تب بھی شور مچتا ہے۔ مہاجن جب قرضہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرضہ لے جائیے مگر پیسہ کہاں خرچ کریں گے وہ ہم طے کریں گے اور اس کو مان کرکے سر جھکا کر یہ لوگ چلے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روپیہ لے جائیے اور اس سے ہمارے یہاں کی بنی ہوئی ٹیری کاٹ کی ساڑیاں خرید کر ہندوستانی عورتوں کو پہنائیے تو ہمارے کپڑے کی صنعت تباہ نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ کھاد کے اوپر سے سبسڈی اٹھاؤ جو اٹھا دی جاتی ہے تو کیا کھاد کے دام بڑھیں گے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی پالیسی اختیار

[SHRI MOHD. AMIN.]

کرو تاکہ مزدوروں کی چھنٹی ہو تاکہ لوگ بیکار ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روپیہ لینا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری کارخانے جو نقصان میں چل رہے ہیں۔ ان کو پرائیویٹ کے حوالے کر دو۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار کے پاس اس وقت کل ملا کر کے ۱۳۴ ادیوگ ہیں۔ اس میں سرکاری حساب سے ۹۸ ادیوگوں میں نقصان ہوتا ہے اور ۳۶ میں آج بھی منافع ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی۔ اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تھا کہ ان ۳۶ ادیوگوں میں جو منافع ہوتا ہے وہ ۹۸ کے نقصان کو قریب قریب پورا کر دیتا ہے لیکن سرکار ایک طرف بی۔ آئی۔ ایف۔ آر۔ میں بھیج رہی ہے معاملات کو اب یہ جو آپ کا موٹر کا کارخانہ تھا ماروتی یہ نفع میں چل رہا تھا۔ شری مہودے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں تو اس کو کیوں پرائیویٹائز کیا۔ اس میں تو نقصان ہوتا تھا۔ یہ ورلڈ بنک کا کرشمہ ہے ورلڈ بنک کا کھیل ہے۔

اپ سبھا ادھیکش: شریمتی سشما سوراج۔ اب سماپت کریئے۔ سمے ہو چکا ہے

شری محمد امین: میں تو ریلیونٹ باتیں کہہ رہا ہوں۔

اپ سبھا ادھیکش: ریلیونٹ باتیں کہہ رہے ہیں لیکن سماپتی کی طرف بڑھیئے

شری محمد امین: مجھے پانچ سات منٹ اور دے دیجئے۔

اب یہ پرائیویٹائزڈ کا جو جھگڑا چل گیا ہے۔ اخبار والے بھی شور مچا رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن۔ پرائیویٹائزیشن۔ پرائیویٹائزیشن۔ کیا ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ۳ لاکھ کل کارخانے بند ہیں پورے ہندوستان میں یہ سارے کے سارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر اتنا ہی قابل تعریف ہے تو اتنے کارخانے بند کیوں ہیں۔ اصل بات وہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ سرکار کی پالیسی غلط ہے اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں فولاد کے جو کارخانے ہیں ان کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اس سے بہت کم پیدا ہو رہی ہے اور سرکار ودیشوں سے فولاد منگواتی ہے۔ ودیشی مدرا خرچ کرتی ہے۔ پیپر انڈسٹری کو آپ دیکھیں۔ ۵۰ کارخانے ہیں ہندوستان میں جن میں ۲۵ کارخانے بند ہیں۔ بند اس لئے نہیں ہیں کہ اس کے لئے بازار نہیں ہیں کاغذ کا بازار بہت اچھا ہے لیکن راہ میٹیریل کی کمی ہو گئی ہے۔ را میٹیریل کا انتظام نہ کر کے کارخانوں کو بند کر دیا گیا مزدوروں کو بھوکوں مرنے کیلئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ہانگ

کو لیا گیا ہے کیونکہ سرکار نے پلاسٹک سے کاغذ والوں کو ... اس طرح سے سنتھیٹک انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کا لائسنس دیئے گئے ہیں۔ دلی میں ہریانہ میں اور نہ جانے کہاں کہاں سنتھیٹک پیکیجنگ میٹیریل سستا پڑتا ہے لیکن اس سے جوٹ کی صنعت برباد ہو رہی ہے۔ بہت لوگ یہ سوچ رہے ہونگے کہ پچھمی بنگال میں بائیں بازو کی حکومت ہے وہ مصیبت میں پارٹی تو ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جوٹ کی صنعت میں کام کرنے والے ۵۰ فیصدی لوگ غیر بنگالی ہیں بہار، اتر پردیش، آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے ہیں یہ سارے لوگ پریشان ہیں کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ اپنی صنعت کو برباد کرنے کے راستے پر کوئی سرکار جا سکتی ہے جس کو اپنے دیش سے اپنے لوگوں سے اور اپنے مزدوروں سے محبت ہو۔ اس طرح سے آواز بھی اٹھا ہے ہم لوگوں کی پچھمی بنگال کی اسمبلی کے ممبروں کی ایک میٹنگ ابھی پانچ چھ مہینے پہلے پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی تھی پرائم منسٹر جی نے یہ کہا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے ۱۳ سرکاری کارخانے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ۸ میں نقصان ہو رہا ہے اس لئے آپ ایک ایک کارخانے کو لے کر بیٹھئے ہمارے ساتھ بھی یونینس ہیں انکو بھی بلا لیجئے کیونکہ یونینس کی بات آپ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ بیوروکریٹس چلاتے ہیں اور بیوروکریٹس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جال پھیلایا ہوا ہے۔ اس لئے نقصان ہوتا ہے۔ آج تین لاکھ کارخانے بند ہیں۔ ان کے بارے میں ریزرو بینک نے ایک سروے کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مزدوروں کی وجہ سے صرف دو فیصدی کارخانے بند ہیں۔ ۹۸ فیصد کارخانے اس لئے بند ہیں کہ کہیں را میٹیریل نہیں ہے کہیں فائنانس نہیں ہے اور کہیں بازار نہیں ہے اس مینیجمنٹ نہیں ہے اور کرپشن ہے بے ایمانی ہے اس لئے اگر یونینس کے ساتھ بیٹھا جائے تو مزدور اپنی روزی کا خیال رکھتا ہے وہ ساری سچی بات آپ کو بتا دیں گے۔ اگر ان کی باتوں کی روشنی میں اقدامات کئے جائیں تو جو کارخانے آج نقصان میں چل رہے ہیں وہ کل نفع میں چل سکیں گے یہ ہونا چاہئے تبھی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں۔ دو سوال ہیں جو اس وقت ہندوستان کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک ہے مہنگائی اور دوسرا ہے بے روزگاری ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ ... لینڈ ریفارمس سے اگر ... لینڈ ریفارم ہو جائے زمین کسانوں کو مل جائے کسانوں کی قوت خرید بڑھے گی اور کارخانوں کا بنا مال ... سب کا سب

[SHRI MOHD. AMIN.]

[illegible] گاؤں ہزاروں سینٹر کارخانے آپ کو بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کو کام ملے گا۔ بیسک لینڈ ریفارم کے بارے میں نہ تو بیروزگاری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی سرکار اس بات کا دعویٰ کرے کہ مہنگائی کم کر دیں گے تو یہ غلط ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہوگی اور اسمیں کبھی سپھلتا نہیں ملیگی۔

ان چند شبدوں کے ساتھ میں یہ ریزولیوشن سدن کے سامنے رکھتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اسکو منظور کیا جائے۔

THE QUESTION WAS PROPOSED

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : उप सभाध्यक्ष महोदया सदन में महंगाई से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और चर्चा में जो मुख्य एक मुख्य प्रश्न है वह यह है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई के बढ़ने से गरीब तबके के लोगों, मध्यम श्रेणी के लोगों, मजदूरों, बंधी हुई तनख्वाह पाने वालों और मध्य कर्मचारीगण जिनकी आमदनी बहुत सीमित है उनके घर परिवारों में महंगाई के वजह से हाहाकार है। औरएक तरह का अजीब वातावरण बना हुआ है और महंगाई कहीं रुकती नजर नहीं आ रही है उस पर कोई अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है । महंगाई बढ़ने के जहां और बहुत से कारण है वहां यह भी है कि जिस स्थान पर जिस क्षेत्र में, एरिया में कुछ सूखे की शिकायत हो जाए, कुछ अकाल का वातावरण पैदा हो जाए, "वक्त पर वर्षा न हो तो पैदावार में फसल में कोताही हो जाती है तो अक्सर दाम बढ़ जाते हैं खाने पीने की चीजों के और जो फसल से चीजें मिलने वाली हैं उनके लेकिन देखा गया है कि जो दाम बढ़ गया जो दाम चढ़ गया उस कोताही के वक्त में, कमी के वक्त में शार्टेज के वक्त में, उसके विपरीत अगर बम्पर फ़सल भी हो गयी, वर्षा भी ठीक हो गयी अकाल आदि का भी कोई वहां पर असर या प्रभाव नहीं है, चारों तरफ से कमोडिटीज अवेलेबुल हैं तब भी दाम उतर-कर नीचे नहीं आते हैं तो जैसा मैंने कहा कि सारे देश के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं जो बंधी तनख्वाह पाने वाले हैं, मध्यम श्रेणी के कर्मचारीगण हैं जिनकी तनख्वाह सीमित है, आमदनी सीमित है आज उनके घरों में महंगाई के कारण जो तड़पन है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। इसका अंदाजा तो वे लगा सकते हैं जो टोकरी लेकर सामान खरीदने बाजार में जाते हैं। सब्जी खरीदते हों, दाल आटा खरीदते हों घी खरीदते हों, सरसों का तेल खरीदते हों। महंगाई का आंकड़ा जब सैटिसफाई करने की बात आती है तो उसमें फ़र्क हो जाता है । बाजार कुछ कहता है और पेपर कहता है कि चीज का दाम यह है । अखबार में रेट कुछ रहता है और बाजार में भाव कुछ रहता है । तो जैसा मैंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है । इसके लिए कोई एक नीति बनानी पड़ेगी और वक्तन-फ़क्तन, एक महीने दो महीने के लिए, बल्कि हमको मार्केटिंग प्रोसेस ऐसा करना है कि 15 दिन के लिए मार्केट में जो प्राइस हैं उसको हमको डिक्लेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए । ये सारी चीजें और मेकेनिज्म डेवलप करने चाहिएं क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है जो मजदूरों का है किसानों का है । यहां की जो पापुलेशन है, आबादी है गरीब लोगों की है। उनको आप छोड़ दीजिए जो 20 प्रतिशत बड़े रईस राजा लोग हैं। वे पैसे खर्च कहां करें यह उनके दिमाग में सवाल है और दूसरी तरफ़ यह सवाल है कि हम अपने पेट का पालन पूरा कैसे करें, हम अपने घर परिवार का पालन कैसे करें । इन दो सवालों में हिन्दुस्तान की आबादी घूमती है, चक्कर खाती है । तो यह

महंगाई का जो प्रश्न है इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को बहुत मजबूती से मार्केटिंग का जो मेकेनिज्म है उस पर कंट्रोल करना चाहिए और यह कैसे हो। इसके लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी हो। साधारण गांव में रहने वाले लोगों की हो, यूनियन टेरीटरी में रहने वाले लोगों की हो, सांसदों की हो। इन सबका रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि सचमुच में एक एक्चुअल प्रेक्टिस की जो चीजें हैं वे सामने लाकर रखें। तब ये चीजें होनी चाहिएं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी कमोडिटीज हैं। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, आम तौर पर मिडिल क्लास के लोग, लो क्लास के लोग और मजदूर भी कुछ न सही तो एकाध कम्बल खरीदते हैं, कोई ऊनी स्वेटर खरीदते हैं। उस पर जो टैग लगा होता है उसको कोई देखने वाला नहीं है कि इतना ऊन इसका है भी कि नहीं, इतना उसका दाम है कि नहीं। इतना अंधा व्यापार ऊन में चलता है। जो स्वेटर पर गलत कीमत लग जाती है वह भी सही है। कंज्यूमर से कहते हैं इसका तीन सौ रुपए दाम है। मालूम पड़ता है कि सौ या पचास रुपए का तो नहीं है लेकिन अगर उसमें टैग तीन सौ रुपए का लग जाएं तो तीन सौ रुपए से कम नहीं लेंगे। आखिर यह जो जेब कटी का काम है जो इस कीमत पर होता है जो लोगों की जेबों को काटा जाता है सिर्फ कागज पर कीमत लगाकर इस पर कैसे अंकुश लगाना चाहिए? सरकार को इसमें सख्ती से कोई तरीका निकालना चाहिए। सारे मार्केट के अन्दर चले जाइये, कपड़ा खरीदने जाइए। अंधा व्यापार है। 16 रुपए मीटर, 40 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर है। लेकिन कहां लिखा है। कहां है इसका रेट? मुझे थान पर बताओ। कहीं थान पर दाम नहीं मिलता। पर मीटर का दाम कहीं नहीं लिखा होता। हमारी आधी से ज्यादा आबादी तो बिना पढ़ी है जिनको ज्ञान ही नहीं है। कपड़ा एक, स्टफ एक, मशीन एक, कम्पनी एक लेकिन अगर रंग में चमक दमक का फर्क आ गया और च्वाइस में अगर एक अच्छा रंग मालूम कर लिया तो उसी का दाम बढ़ा देते हैं लोग। तो यह जो लूट का मार्केट चल रहा है। प्राइस पर इस पर सरकार को प्रैक्टिकल व्यू लेना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर सैटिसफाई करने का जो तरीका चल पड़ा है, यह इन्फ्लेशन हुआ था, यह इन्फ्लेशन नीचे आ गया, यह इन्डेक्स था, सरसों का दाम यह था, यह हो गया, यह प्रैक्टिकल नहीं है, अमली नहीं है। यह सच्चाई पर पर्दा डालना है। सारे देश के अन्दर महंगाई को लेकर जो बेचैनी है उसका अंदाज तो मेरे जैसा आदमी जो कामन आदमी है, जो घूमता है, जो बैठता है उठता है, जो उनके दृष्टिकोण को सुनता है, वह जानता है। जो दिल्ली के बड़े-बड़े एयर कंडीशंड कमरों में बैठते हैं उनको इसका अंदाज नहीं है कि महंगाई क्या कहर मचाने वाली है और मैं यह कहना चाहता हूं, सरकार को वारनिंग देना चाहता हूं अगर इस बीमारी पर बहुत जल्दी काबू नहीं पाया गया, इस लाइलाज बीमारी को लाइलाज बनाते चले गए तो सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। चूंकि आखिर हिन्दुस्तान में गरीब लोग हैं। आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिए। नहाने का साबुन टाटा, बिरला, डालमिया, लीवर यानी कौन-कौन सी कम्पनियां बनाने वाले, बड़े से बड़ा भी काम करती हैं और छोटे से छोटा काम करती हैं, कंघा भी बनाते हैं, मंजन भी बनाते हैं, ब्रश भी बनाते हैं और साबुन भी बनाते हैं। दाम बढ़ जाता है। साबुन का भी जो कामनमैन सोप है, जो कन्ज्यूमर आइटम है, उसका दाम भी बढ़ जाता है और उसका वजन घट जाता है। डिज़ाइनिंग में आधा इंच और साबुन कम कर देते हैं, कोई देखता नहीं इस बात को कि तुमने जो उसका दाम बढ़ा दिया, तो उसका वजन कम क्यों हो गया —ऐसा

चौधरी हरी सिंह

डिजाइनिंग क्यों करते हैं, जो साबुन का वेट घट गया?

आखिर इन सब चीजों को देखना होगा। दवाइयों, गोलियों को देखिए। उनके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। उसका कहीं कन्ट्रोल नजर नहीं आता। उसके ऊपर भी सबसे बड़ी जो हिन्दुस्तान में बीमारी है, माननीय महोदया, वह यह है कि यहां पर 90 फीसदी मार्केट में एडल्ट्रेटिड चीज बिकती है। एक तो दाम बढ़ा कर जेब काटी जाती है, ग्राहक की, गरीब लोगों की—फिर दूसरा एडल्ट्रेशन करके जेब काटी जाती है।

तो कहने का मतलब यह है कि उसको तो सौ रुपए में सिर्फ 15–20 रुपए मूल्य का ही सामान मिलता है। आप जहां भी जाइए, हर जगह स्पूरियस ड्रग्स हैं, अरहर की दाल में मिलावट है, चावल में खाने को होते हैं सफेद पत्थर। अब हमारे वह कहां गए अमीन साहब, अगर सही माने में हम देखें, तो खाने की चीजों में मिलावट के जो पत्थर हैं, दालों में मिलाने के जो पत्थर हैं, जो कंकड़ी हैं, वह सारी बंगाल में ही बिकती हैं। अगर चावल में सफेद पत्थर मिलाने के लिए किसी व्यापारी को जरूरत है, तो कलकत्ते और बंगाल की मार्केट से ही वह आता है। तो बंगाल जो है, वह तो मिलावट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है—दालों के लिए और चावलों के लिए। ऊपर से दाम बढ़ रहे हैं और मिलावट का बड़ा जोर है।

यह सब हमको देखना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए। दूध की, पानी की, इसकी बात तो अलग रही, आखिर महंगाई को अगर हम बेतहाशा बढ़ते चले जाने देंगे, तो मैंने जैसा कहा, कि यह हमारे सामने बड़ा टेढ़ा सवाल खड़ा हो जाएगा।

किसान की फसल आती है तो दाम कुछ नीचे रहते हैं। अब जो बड़े–बड़े किसान हैं, वह भी अपने घर में फसल रखने लगे हैं और एक वह जो बीच के बिचौलिए हैं—जो न किसान हैं और न व्यापारी हैं, बीच में एक मिडल–क्लास और पैदा हो गई है जो सिर्फ मौके का महज फायदा उठाकर अपने यहां अनाज रख लेते हैं और फिर दाम बढने पर उसको बढ़ाते हैं।

अब इस सरकार को देखना चाहिए कि जो ये नए बिचौलिए पैदा हो रहे हैं, जो न किसान हैं, न सचमुच ट्रेडर्ज हैं और व्यापारी भी नहीं हैं, सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए हैं, इस क्लास को रोकना चाहिए।

गरीबों को घर, मकान, दवा-गोली, इलाज, कपड़ा—इन सब की बहुत जरूरत होती है। मकान बनाने के लिए सैकड़ों स्कीम्स जो है तरह–तरह की, वह सरकार भी निकालती है, राज्य सरकारें भी निकालती हैं, व्यक्ति विशेष भी निकालते हैं, कैपिटलिस्ट्स की तरफ से भी मकान बनाने कि स्कीम्स होती है।

अगर आप देखें, जो हमारी हाऊसिंग की स्कीम्स राज्य सरकारों की और केन्द्रीय सरकार की है, अगर गरीब आदमी महंगाई की वजह से या किसी और आर्थिक संकट की वजह से अपनी किश्त न दे पाये, तो उतना उसका सूद होता है। अगर किसी ने मकान कंस्ट्रक्ट किया सौ गज या 150 गज का और उसकी वक्त पर दो किश्त न दे पाया, तो उसके सूद और पनिशमेंट का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि बैंक का तीन गुना चार गुना देना पड़ता है इस पर अगर वह कहे कि हमको मकान नहीं बनाना है, छोड़िए—हम रुपया नहीं दे सकते, महंगाई की वजह से हमारी कमर टूट गई, जेब कट गई—हम इसका रुपया नहीं पहुंचा सकते, अपना रुपया वापस लेना चाहते हैं, तो

उसमें से भी वह बीस हजार में से दो हजार काट लेते हैं—यानी होना तो यह चाहिए कि आपने उनके रुपये का दो, छह, आठ, इस साल तक सूद खाया। आपने दूसरे गरीब मजदूर, किसान और मध्यम श्रेणी के कर्मचारी का रुपया अपने पास रखा और जब वह वापिस लेता है, बेचारा, तो दो हजार रुपया उसका आप काट लेते हैं। एक तो सूद इतना, अगर कहीं से इंतजाम करके वह दे भी दे, तो वह गरीबों के जो मकान बनाने की स्कीम हैं, इसको भी रिवाईज करने की आवश्यकता है—पालिसी के तौर पर और प्रैक्टीकली भी।

इसको सदन के माननीय सदस्य देखें कि इस हाऊसिंग स्कीम के सूद की जो दर है, जो पनिशमेंट की दर है, जो एलाटमेंट की दर है, यह सारे सदस्यों को देखना चाहिए। घर बनाना तो सब पार्टियों का काम है। घर मुहैया करना, कपड़ा दिलवाना, शिक्षा दिलवाना यह तो सब पार्टियों के मैनिफ़ैस्टो में है, यह उनका धर्म और मजहब सब कहता है और सब दिल से चाहते भी हैं।

तो यह जो मकान, जो हाउसिंग पालिसी में हैं, इतना बड़ा भ्रमजाल, जिसमें मैं रोज देखता रहता हूं नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अन्दर, लखनऊ में गोमती के किनारे—दो किश्त नहीं पहुंची तो जो, मूल जमा किया, उससे ज्यादा, दुगुना—तिगुना हो जाता है। तो हाऊसिंग पालिसी के इस एमपैक्ट को पूरे सदन को बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। अमेंडमेंट लाकर के जो भी रास्ता निकल सकता है, लाना चाहिए, जिससे गरीब लोगों को, छोटी तनख्वाह पाने वालों के, मजदूरों के, जो बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पर मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, वह भी अपना छोटा सा घर 50—100 गज में बना सकें।

यह सब तभी हो सकता है जबकि हमारी हाऊसिंग पालिसी ठीक हो।

जब मैं महंगाई की बात कहूंगा तो ..... आप उत्तर प्रदेश के साथी नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं निष्पक्ष भाव से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सफ़ाईकर्मी हैं, उनको 6—6 महीने तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। दुकानदार भी उधार नहीं देते। किस संकट में बेचारे स्वीपर और सफ़ाई—कर्मी दिन काट रहे हैं, इसका अंदाज लगाना कठिन है। उनको 6—6, 7—7, 8—8 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही, महंगाई भत्ते की तो बात छोड़ दीजिए, वर्दी की बात छोड़ दीजिए और करीब डेढ़ लाख जो सफ़ाई-कर्मी काम कर रहे थे उनकी छंटनी कर दी गई और बेरोजगारी और बढ़ा दी। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही हैं और उनका जो जी० पी० एफ० जमा है वह नहीं मिल रहा। शादी के लिए यह रुपया जमा किया हुआ है वह उन्हें नहीं मिल पाता। इन सारी मुसीबतों में ये जो गरीब तबके के लोग हैं इस मंहगाई के समय में दोहरी मार से मर रहे हैं, रुपया—पैसा मिल नहीं पाता, कर्ज मिल नहीं पाता, ऊपर से यह महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। यह सारे सरकारी जो हमारे काम के हैं उन सबको इसका अंकुश अगर बहुत तेजी से नहीं लगेगा तो यह हमारा रास्ता नहीं सुधर सकता। इसके साथ—साथ, मैं 2—3 चीजें और कहना चाहता हूं जो कि यह बहुत आवश्यक है कि हमारे यह कपड़े के बारे में जैसे मैंने कहा कि यह निश्चित तय कर देना चाहिए हर मीटर पर कपड़े का दाम लगा हो, स्टाफ़ जो बना हुआ है उसका भी यह परसैंटेज हर मीटर पर कहीं तो आने पर लिखा रहना चाहिए। यह नहीं कहता कि दाम का जो यह प्रोसेस मार्केट में है इसको स्टाप करना चाहिए।

ये मेरे चन्द प्रैक्टिकल सुझाव हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन्हीं अलफ़ाज

चौधरी हरि सिंह

के साथ यह जो प्रस्ताव है यह बड़ा आंख खोलने वाला मैं समझता हूं और इससे जरूर देश की महंगाई पर एक अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा अनुमान है ।

श्री मोहम्मद अमीन : एक बात मुझे पूछनी है, अभी जो आनरेबल मैम्बर····· **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज आप बाद में रिप्लाई देंगे ना उस समय कह लेना ।

श्री मोहम्मद अमीन : नहीं, यह सवाल एक ····· **(व्यवधान)** उन्होंने यह तो बहुत सही फ़र्माया है कि चावल में पत्थर की मिलावट होती है लेकिन यह जो इन्होंने कहा है कि यह काम कलकत्ता में ही होता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कलकत्ते से ही चावल की सप्लाई सारे हिन्दुस्तान को होती है ?

†[شری محمد امین: نہیں یہ سوال ایک... "مداخلت"... انھوں نے یہ تو بہت صحیح فرمایا ہے کہ چاول میں پتھر کی ملاوٹ ہوتی ہے لیکن یہ جو انھوں نے کہا ہے کہ یہ کام کلکتہ میں ہی ہوتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کلکتہ سے ہی چاول کی سپلائی سارے ہندوستان کی ہوتی ہے۔]

चौधरी हरि सिंह : वह पत्थर की सप्लाई होती है। ···· **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : वह पत्थर की बात कर रहे हैं। ··· **(व्यवधान)**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन। ··· **(व्यवधान)** अमीन साहब इस तरह से नहीं, अगर आपको कुछ कहना है तो जवाब के समय कहिए।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh) : Madam Vice-Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the subject. I rise in this House to support the Resolution which has been moved by my honourable colleague from the CPM party, Mr. Mohammed Amin.... (*interruptions*) ...

The BJP is supporting a CPM Member's Resolution because I believe in this House. .. (*Interruptions*) ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Many times it has happened.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Dr. Jain is supporting it for the first time.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : It has become our tradition to focus our attention. ..(*interruptions*) ..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : हनुमन्त राव जी, वह सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। जैन साहब को बोलने दीजिए।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : It has become a popular practice in this House to focus our differences. There are friends like Mr. Narayanasamy who oppose whatever I say. But I wish to request and I wish to appeal to the sanity of this House that on some issues like price rise, protecting the poorer sections of our society, all of us should have a duty and unanimity in requesting the Government and in persuading the Government to have a policy which is helpful to them. Though we are loyal members of various political parties, yet, our ultimate loyalty is to the people of India and to our great country. In that spirit, Madam, I support the Resolution moved by my CPM friend.

I also wish to say a few points on the inflation issue. While every common man understands that the prices are going up, when we read the Government figures, it says : "No,.... inflation is coming down." Now, the Government claims that the rate of inflation has been reduced to a single-digit figure and all. I do not claim to be a student of economics. There is no provision for reading economics in the medical curriculum. But I am an ordinary man and every ordinary man of this country, today, is

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

perturbed and cannot see any rationale in the plea of the Government that it is able to control inflation while, in the day-to-day life of an ordinary family, the price-rise is playing havoc. Madam, I tride to understand this and I wish to share my understanding with the hon. Minister of State for Finance. I want the Minister of State for Finance to kindly appreciate this. The November-end figures are here. While the wholesale Price Index went down by 0.31 per cent, the prices of primary articles went up by 0.1 per cent and the prices of food articles went up by 0.3 per cent. I will not go into the statistics and the jugglery of economists. I just wanted to illustrate the point that while you are able to arrive at a total inflation, on the basis of calculation, to show that it has a downward trend, the factors which affect the common man, that is, the prices of food articles, which are the necessities of the poorest of the poor and everybody, are more in their magnitude. That is, the prices of all the primary articles are going up. What is coming down then? Coming down is the industrial production; and, this means recession because of the lower demand and lower industrial production. The Government should recognise that this kind of inflationary trend also is a component of the industrial recession. People are becoming so poor that they will not be able to purchase and that is the reason why all our industrial production is becoming stagnant now. And, this sort of inflationary lowering down is not providing relief to the majority of our population because their demand is for food and primary articles. The prices of all these things are going up. And, tomorrow, even this will not be manageable because the industrial production will further come down and I do not know what magic formula our Finance Minister has to deal with the situation.

Madam, I support the contention of the previous speakers, including Chowdhry Hari Singh, that no relief is being provided to poorer groups. The recent hike in the prices of petroleum products and fertilizers has further increased the burden. What is worse is, madam, after two months or so, we will have the Budget. The Finance Ministry must have already started working on it. I am reading some figures every day in newspapers. When I read that the Railway Ministry is trying to collect a further revenue to the tune of about Rs. 150 crores, when I read the news that the Govt. is thinking of further raising the prices of petroeum products and others and the administered primes that are controlled by the Government are being incerased, I am shocked. Who is responsible for the increase in prices? The Government. All such prices which are being controlled by the Government are being increased. "And, who are becoming the victims of these Government policies? The common people, the poor people and the ordinary citizens of this country. So, the Government has the major responsibility. Madam, I wish to request the Government to kindly control the prices, at least such prices which are controlled by the Government, and arrest the price-rise which is hitting the common man. I want to take you to a new dimension of our economic development which is related to the stark reality of population. I have never been a follower of Rajiv Gandhi. But I wish to remind the Ministers of the present Government that they should read the Rajiv Gandhi Memorial Foundation lecture which was delivered by Robert McNamera here on the invitation of the Rajiv Gandhi Memorial Foundation. This lecture is an eye-opener to any conscientious citizen. I recommend that all parliamentarians should read that lecture. I want to quot one reality of that lecture in order to enlighten the Members as to on what threshold of destruction we are standing today. Madam, all of us know that we are more than 870 million people today. Mr. McNamera, the former President of the World Bank, who remained with the World Bank for 30 years, who is a very knowledgeable person, a learned economist of our time, has calculated the figures. He says : "If the present population policy of our Government succeeds--we know that we are not succeeding, we are failing on the population-control front-as per our decided target, in the next thirty years, we would have added more than 430 million people to our existing population." Madam, I warn the Government against this I would request the Government to consider this and ponder over this

[DR. JINENDRA KUMAR JAIN]

question seriously. "You can see the consumption pattern of such a large number of people and the consequent effect of such consumption on environmental degradation." He says this and all our Government departments agree with this. I raised this issue with the Ministry of Health and Family Welfare and they concurred with this that this country is not sustainable economically. If this nation will not be sustainable economically and from the development point of view, what are we doing about it? We are going to have such a large population in such a small land area and the task of maintaining such a large population is itself a formidable job and the Government should take it seriously. There is a unanimity among all parties that something should be done. But I am sorry to say that beyond lip-sympathy, beyond rhetoric, the Government is not doing enough for this. I don't say that it is the responsibility of Government alone. I, on behalf of my party, and on my own behalf, am willing to contribute and support it fully but all of us must work unitedly and vigorously to take care of some of the issues which are very fundamental to the economic development of our country, including the price rise and do something about it.

Now I come to another dimension of my presentation that I wish to share with the learned Members of this House, that is in a country, in a society who should be more powerful-people or the State? I have been thinking on this issue. During the last recess of Parliament, I had an opportunity to go abroad. I was in certain cities of America, I was in England, I was in France and I was in Russia. It was a short trip and I had to come back to India. I was seeing a pattern-the pattern of economic development--and I noticed that wherever the State was stronger than the people, the economic development has not taken place. And wherever the ordinary people were having more powers to look after themselves, more economic prosperity has taken place. After seeing this, when I come back to my country I find that ours is a poor country.

We are poor people but we, being poor people, have to support a very expensive Government. Can we afford to have such an expensive Government? The Prim Minister agreed to it in a debate like thi last year. He made a promise in thi House, "Yes, the administrative expense of the Government have to be cut down." He gave a directive and informed us tha he had directed that the administrative expenses should be cut down by ten pe cent. I know it has not been done. want to know from the hon. Finance Minister whether he is not able to dc what his Prime Minister wants him to do whether the situation is beyond their control or they don't even take the Prime Minister's directive seriously as they don' take many of our requests seriously. Madam, I wish to make a simple submission. ...(*Interruption*)... I will finish very soon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMAT SUSHMA SWARAJ) : You still have twc minutes.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : I submit that these poor people cannot afford to have such an expensive Government and I urge upon the Government to reduce its size, curb its expenses and spare the people of India from its extravagant way of living.

Madam, I want to make one more comment on the Government's Economic Policy. We had, as a Party, welcomed the liberalisation and the process of deregulation. But what do we find today? I request you to appreciate the opposition to the Economic Policies of the present Government that my friends from the Left Front and National Front and the BJP put up. While they are opposed to the very process of liberalisation, the BJP wants liberalisation but we want a true liberalisation and we want a true deregulation of the Indian economy. But whose liberalisation do we want? Our concept of liberalisation does not mean that this country should have a free-play of all international forces and multinational forces. We want liberalisation of the Indian people from the shackles of regulation and various Governmental procedures that you have tied around us. Today what is happening in the new dispensation of the Economic Policies?

The Government of India has created two classes of citizens in India or there are two types of procedures. One procedure is for the Indians who are still having all kinds of controls and regulations. But we have given a free play to the foreigners or to the international citizens. Madam, today Indians are being beaten in their own marketplace, that is, in India, but you have given every freedom to the foreigners or the international citizens--you may call them N. R. Is. Indians in their own country, in their own market-place, are at a disadvantage and foreigners and international citizens can have every privilege over here! This is not our understanding of liberalisation. We want Indian entrepreneurs, Indian traders, Indian industrialists, Indian hard-working people, Indian labour class to have freedom to work for their economic development. That is being denied to them. Madam, BJP liberalisation is very different from the Congress liberalisation. .... (*Interruptions*) ...... Madam, I am making my last point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : And then conclude. .. (*Interruption*) .. Mr. Narayanasamy, you are going to speak after him and then say whatever you want to saw. Then you elaorate what the Congress liberalisation is.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra) : Madam, I don't understand the difference between the Congress liberalisation and the BJP liberalisation. Liberalisation is liberalisation... (*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, he should also liberalise his policies...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Mr. Narayanasamy, I am saying you are the next speaker. You say whatever you want to say in your time. Let him conclude now. ...(*Interruptions*)... Let him conclude now. Madam, I am concluding by making this last point. My observation is that there has been too much of concentration of powers in the hands of the Central Government on our resources related to economic development. I will give you only one example of Madhya Pradesh because I represent Madhya Pradesh here. Take, for example, electricity generation. We want electricity for economic development. We have calculated the power requirement of Madhya Pradesh and for generating the amount of power we need. we require Rs. 40.000 crores. The Planning Commission does not have that much money to give to our State; the Power Financial Corporation does not have that much money to give to our State. Now, we have a policy that we can invite the private sector to do it. A licence was granted to the Madhya Pradesh Electricity Board by the Central Government and they said that we could have our own plan. The Madhya Pradesh State Electricity Board had transferred this to the private sector more than a year ago. This has, not been honoured by the Central Government in the last one year. The Central Government says, 'come again' and their Energy Ministry says, 'come again'. It takes four to five years for a major ministry to grant a licence and the State Government has to go to it again and again. Electricity is not something which can be produced by ordinary people. It has to be given to a large sector. The policy is there. Though there is a policy of allowing the private sector to generate electricity, in practice the bureaucrates and the Central Government by the backdoor hold the power 'and not allow the economic development to take place. I close by making a request, through you, to the House that it should recommend that a time has come to loosen the hold of the Central Government on the powers and resources necessary for economic development. Let the State Governments also have their due share and allow them to develop their resources, like mineral resources and other natural wealth which the Almighty has given us and which have not been developed and utilised for the betterment of the life of the people of our country because of the faulty policies, the defective Nehruvian economic vision, pursued so far ever since we achieved political independence.

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam Vice-Chairman, I thank you for giving me this opportunity. I partially support the Resolution moved by the hon. Member, Shri Mohammed Amin. The rise in the price of essential commodities is an accepted fact as far as the political parties and

[SHRI V. NARAYANASAMY]

the public are concerned. The arguments from the other side seem to be that it is only this Government that is responsible for the price rise. This cannot be accpeted. There are various factors which are responsible for the rise in the prices of various consumer items. Today the common man is facing the problem, especially the middle class and the lower middle class and the people below the poverty line They could not even meet the requirement of two meals a day because of the sharp increase in the prices of essential items. There is no quarrel as far as the increase in the prices of essential items is concerned. What are the factors that are responsible for the rise in the prices of these items? We know that in 1989, when the Congress Government led by the late Rajiv Gandhi went for elections, the foreign exchange reserve was more than Rs. 6,000 crores. Then the National Front Government supported by the BJP and the Communist Party came to power. The economic situation in the country was not tackled properly. Not only that, there was also the Gulf War and the Government increased the prices of petroleum goods because of which the prices of all other items increased and the inflationary trend worsened. In 1988, it was single digit when the Congress Government was in power. It increased to 17.1 per cent within a period of eight months after the National Front Government took office. Madam, I am not blaming them for this for the simple reason that the National Front Government had no time to tackle the economic situation in this country. There was inner wrangling in the political field between the Janata Dal leader on the one side, the BJP and the Janata Dal party on the other side. They had to resolve their political problems, Therefore, the National Front Government did not tackle the economic situation properly. Therefore, Madam, the inflationary trend continued. Thereafter, the Chandra Shekhar's Government took office. Madam, we are all aware that the country's valuable and precious gold was mortgaged with foreign countries for the purpose of meeting even the day-to-day affairs and the day-to-day expenditure of this country. They did not even have cash reserves for two weeks. There was a situation where our Government's credibility was at stake. The foreign countries were not prepared to advance loans to India, even on a short-term basis. That was the state of affairs when Chandra Shekar's Government was in office. Thereafter, the Government led by our Prime Minister took office. That was about 18 months back. By that time the economic situation in this country was in a bad shape. The foreign exchange reserve that we had was only Rs. 2000 crores. It was bad when compared to the previous years. When Chandra Shekhar left office and we took over, it was very less, it was about Rs. 2000 crores or roughly about Rs. 2,300 crores. In the history of our country our foreign exchange reserve was never as low as that, right from Panditji's time to the time when Shri Rajiv Gandhi was our Prime Minister. There were various factors which were responsible for the increase in the prices of essential items. The present Government, with the available resources and with the help of foreign assistance wants to improve the economic situation. In this world. when the developing countries are changing their economic policies to suit the present economic situation that is prevailing in the world if India lags behind without adjusting its economic policy, then, we will never improve our situation.

The best example of a country where economic liberalisation was not fully followed was Russia. Russia was rigid; they followed the Communist policy. Ultimately they suffered and their country disintegrated. Today a country which is having a sophisticated weaponry system is not considered to be powerful country. A contry which has got a powerful economic base is considered to be the most powerful country in the world. Therefore, India had to change its economic policies without affecting the basic theories that were enunciated by Pandit Nehru. And thereby our economic pattern was devised for benefiting the common man. The system that was evolved, the liberalisation policy that was brought forward in the industrial field, in the export and import fields, started yielding results. But in that process, the Governmen had to mop up resources through external sources and also internal means. For mopping up the resources, the Government had to tap the resources through various ways, like, by increasing the petroleum prices. The

hon. Member has mentioned in his resolution that the prices of petroleum products have been increased. There is a fund called the Oil Pool Fund for the petroleum products. That fund has been kept for the purpose of meeting the contingencies by the Government, arising at the time of purchase of crude oil from other countries. Everybody knows, the hon. Member who moved the resolution also knows, that we are producing not even 37 per cent of the crude oil that is required for our country. The remaining we are importing from various countries to the tune of Rs. 8500 crores. In that process, the reserves are being kept. But because of the deficit Budget that was presented during the earlier periods, the funds were withdrawn to the tune of Rs. 5,000 crores from the Oil Pool Fund. But that fund has to be adjusted for the purpose of meeting the future demands. Therefore, the Government had two options, either to withdraw the subsidy or to increase sharply the prices of petroleum products.

There was a lot of criticism and agitation among various political leaders against this Government over the increase in the prices of petroleum products. I would like to submit that the Government has been giving more than Rs. 6500 crores as subsidy on petroleum products alone. Out of that, the subsidy given by the Government on kerosene alone is Rs. 3500 crores. The Government did not touch the common man's item, that is, kerosene, and that price was not increased. The prices of other items like diesel and petrol, were increased by Re. 1 or 94p. per itre about two months back for the purpose of mopping up the resources in the Oil Pool Fund. Even on petroleum products, even though all the petroleum products are imported from various countries, subsidy has been given by the Government on these products. Only to the tune of Rs. 3000 crores, this subsidy has been withdrawn. This amount was put in the Oil Pool Fund for the purpose of meeting the contingencies. By increasing the prices, the Government will be earning about Rs. 6,000 crores as far as the petroleum products are concerned. The Government was pushed to that corner because of bad management of the economy by the previous Government during the earlier period. But forgetting all this, the hon. Members from the other side are saying that there is a sharp increase in the prices of petroleum products. In the earlier period, we have seen that the prices of petroleum products were increased marginally... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You have to speak, Mr. Hanumantha Rao. You are one of the speakers. Kindly... (*interruptions*) ...

SHRI V. NARAYANASAMY : I am explaining the reason why the prices were increased. In spite of this, if you are not satisfied, I cannot help it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You continue. (*interruptions*)...You have to conclude within one minute.

SHRI V. NARAYANASAMY : How can I conclude within one minute.

I have just completed one portion of ... (*Interruptions*) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Your time is going to be over. You know the time-limit... (*interruptions*) ....

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, this is an important subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : That is true. But there is a time-limit for every speech and for every important subject.

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, Private Members will get liberty only on Friday. .. (*interruptions*) ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : No liberty. You know the rule.

SHRI V. NARAYANASAMY : There is no rule.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : Yes, I can quote. You are a Vice-Chairman. You should know the rules.

SHRI V. NARAYANASAMY : It is the discretion of the Chair... Time-limit is the discretion of the Chair... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : This is the rule-in Chapter 9 - Resolutions. The rule number is 161 and the heading itself is 'Time-limit for speeches'. "No speech on a resolution, except with the permission of the Chairman, shall exceed 15 minutes in duration. "Fifteen minutes...(*inetrruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY : That is not applicable to Private Members' Resolution, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : It is meant for Private Members' Resolutions...(*interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY : I have not completed even ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : That is another thing. There is a rule in the rule-book under the heading "Resolutions". The heading itself is 'Time-limit for speeches'. Rule No. 161...

SHRI V. NARAYANASAMY : We are forced...(*interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : You said there is no rule. I am quoting a rule...(*interruptions*)... Kindly try to conclude...(*interruptions*)... You conclude within three minutes because I am giving two minutes extra. At my discretion, I am giving you two minutes extra. You conclude by 4.00 P.M.

SHRI V. NARAYANASAMY : You are giving two minutes. Thank you for that. Madam, my concern is that while agricultural production is high and the demand from the people for purchasing agricultural products is high, the industrial production in this country is going down. I would like to submit to the hon. Minister that the main reason, apart from other factors, is that the banks are not advancing loans as they have been giving to the small-scale industries--Mr. Minister, kindly hear me on this. The banks are not giving loans to the small-scale industries for the capital investment and also the working capital and they have completely stopped these loans in spite of the directions issued by the Finance Ministry. The bank officials are not using their discretion. By that, the small-scale industries, which have been contributing more to the foreign exchange earnings by exporting more small-scale industrial goods to other countries, are going down. Therefore, Madam, I would like to submit to the hon. Minister that this fact may be taken note of an suitable instructions may be issued to the banks so that industrial production also will increase. On the one side, agricultural production is increasing, but on the other side industrial production is going down. This is one of the major factors for the rising prices of various items in this country.

Madam, it is good that the hon. Prime Minister has identified about 270 blocks under the public distribution system. The public distribution system alone can keep the price situation in a balanced manner and by bringing in the 270 blocks, the prices are kept at a stabilised position and the inflationary trend which was a double-digit figure earlier, has come down to a single digit. The Government policy is to bring it down to 8.3% from 9.1%. I would like to know as to what are the fiscal measures the Government is going to adopt for bringing down the inflationary trend to 8.3%. Madam, the people who have been hoarding and who are engaged in blackmarketing, those who are doing such things in an unscrupulous manner, have been booked and arrested. But I would like to state that there is some sluggishness on the part of the administration, whether at the Centre or in the States. Therefore, I would like to know what instructions the Government is going to give to the various State Governments for booking persons who are involved in hoarding and blackmarketing. Now, I come to my final point.

Madam, there is a demand now from the various State Governments for the inclusion of more items in the public distribution system. In order to control the prices, the States are demanding that more items of essential commodities should be brought under the public distribution system apart from the four or five items that are being supplied to the people through the PDS now. I would like to know what the response of the Central Government to this demand is and what the Government

is going to do about this. Thank you, Madam.

श्री शारदा महन्ती (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे भाई मोहम्मद अमीन साहब ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे देश में 80 परसेंट लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। यह लोग चाहते हैं कि दो वक्त का खाना मिल जाए और सर्दी, गर्मी और बरसात अपने बदन को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए तथा अपने बच्चों के लिए भी दो वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। मगर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कीमतें आकाश को छू रही हैं। आम आदमी तो 6 फुट का है इसलिए उसका हाथ वहां तक जा नहीं सकता। इसलिए इस की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इनका जो मेनिफेस्टो था उसमें यह कहा गया था कि हम 100 दिनों के अन्दर महंगाई कम कर देंगे मगर दिन प्रति दिन महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी को दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। गांवों में आप जाइये। वहां एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे वक्त में जिसको रेवती बोलते हैं, नाल जा बोलते हैं उसको खा कर दिन गुजारते हैं। उसको पकाने के लिए भी लकड़ी की जरूरत होती है। आजकल हर गांव में दरखत नहीं है। लोग काट देते हैं। जंगल में लकड़ी नहीं मिलती है। दूसरी बात यह है शहरों और गांवों में लोग पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। आजकल बिजली का हीटर इस्तेमाल करते हैं मगर बिजली का प्रति यूनिट दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको भी इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ता है। कुछ लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। उनकी हालत यह है कि दो महीने पहले जो गैस का रिफिल 62 रुपये में मिलता था अब वह 93 रुपये का हो गया है। आदमी जो फिक्स्ड इनकम पाता है, सीमित रोजी-रोटी कमाता है, वह इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इसलिए खाना पकाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और हर रोज महंगाई बढ़ जाती है। आज दीवाली, दशहरा या कोई त्यौहार आता है तो आदमी अपने बाल-बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने के लिए जब बाजार जाता है तो वहां यह देखता है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वह अपने बाल-बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकता है। मैं कोई आंकड़ों में नहीं जाता हूं। मगर मेरा यह कहना है कि यह जो महंगाई बढ़ गयी है यह जैसे साइकिल का चक्का घूमता है वैसी ही बढ़ती है। पैट्रोल का जो दाम था वह बहुत ही कम था। हर गांव में हर चीज पैदा नहीं होती है वह बाहर से आती है। अनाज आता है, कैरोसिन आता है, तेल आता है, नमक आता है, सब चीजें आती हैं। पैट्रोल का दाम बढ़ जाने से ट्रक का भाड़ा बढ़ जाता है, ट्राली का भाड़ा बढ़ जाता है, रेल का भाड़ा बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ती है। पैट्रोल का डीजल का दाम बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। अभी हमारा पैट्रोल 18 रुपये पर लीटर है। अभी बजट आयेगा। जरूर पैट्रोल बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पैट्रोल जरूर बढ़ेगा। तो 20 रुपये हो जायेगा। फिर महंगाई बढ़ेगी। अतः गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए। वह बोफोर्स को देखती है, इसको उसको देखती है मगर महंगाई कैसे कम होगी इसको बिल्कुल नहीं देखती है। उनका जो मैनीफैस्टो है उसमें महंगाई, प्राइस राइज कम करना है लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मेरा यह कहना है कि इधर उनको बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। आम आदमी, 80 प्रतिशत लोग महंगाई के नीचे हैं उनको रोजी रोटी हो, दोनों वक्त खाने को मिलना चाहिए, इसको देखना चाहिए क्योंकि जब दोनों वक्त नहीं खाएंगे, उनको स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वे कैसे काम करेंगे, अनाज कैसे पैदा करेंगे, फैक्ट्री में कैसे काम करेंगे। वे तो दिन प्रति दिन बिगड़ जाएंगे।

[श्री शारदा महन्ती]

दूसरी बात यह है कि उनके बच्चा लोगों के लिए जो बेबी फूड मिलता है वह भी दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। वह भी गांव गाव में नहीं मिलता है। सरकार को इसके बारे में देखना चाहिए। बेबी फूड की जो महंगाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है उसको भी कम करना है क्योंकि गांवों में आजकल दूध कम रहता है, दूध नहीं मिलता है और अगर अनाज भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो बच्चा लोगों को कैसे खिलाएंगे। बच्चा लोग देश के भविष्य है, उनको खिलाना पढ़ाना है, उनकी देखभाल करनी है। इसको देखना चाहिए।

तीसरी चीज यह है कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं उनके भाव भी दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। चाहे कोई हास्पिटल हो आप जब जाएंगे तो आपको, आम आदमी को मेडिसिन नहीं मिलेगी, वे लिख देते हैं कि बाजार से खरीद लो। वे बाजार जाते हैं तो उसके दाम इतने होते हैं कि वे खरीद नहीं सकते। उनके बाल बच्चे जो बीमार हैं उनका इलाज नहीं कर सकते हैं।

महंगाई पर हमारे भाई साहब ने बहुत बातें बोल दी हैं। हम लोग जब से यहां सदन में आ रहे हैं उस दिन से सबके सामने महंगाई के बारे में कहते हैं मगर कुछ नहीं होता है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई तो इन लोगों ने बोला था हम कम करेंगे। क्या कम किया? इसको देखना चाहिए कि कैसे महंगाई कम होगी। जो महंगाई है यह राक्षस है जो दिन प्रति दिन हमको खा रहा है। इसको कम करना चाहिए। उन लोगों को बचाना हमारा कर्त्तव्य है। उसके बारे में ये कुछ नहीं करते हैं। मेरा यह कहना है कि यह महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ रही है। इसको जल्दी से जल्दी कम करना है जिससे आम आदमी को हर चीज की सुविधा मिले। यह देखना है यह सरकार का पहला कर्त्तव्य है। अयोध्या कांड, यह कांड, वह कांड, यह नहीं बल्कि वह पहला कर्त्तव्य है आम आदमी को खाना देने का, उसको देखने का। यह कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : The Minister of State for Finance wants to intervene in the debate. I am allowing him. After this we will continue the discussion.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : Madam, I would like to intervene a few aspects. At the outset, I would like to convey my sincere appreciation of the suggestions made by the hon. Members and also the concern shown by some of the Members in regard to increase in prices of certain essential commodities during the last more than one year.

In this regard I would like to mention that the Government regrets that it cannot agree with the views of the hon. Members for the following reasons, particularly with regard to the motion moved by Shri Mohammed Amin.

The first reason is, it does not accept that there is a continuous rise in the prices of all the commodities in the country, putting the common man in great distress. There has been a rise, but I do not agree that there is a continuous rise. I will give the facts. In fact, the wholesale price index for essential commodities in October 1992 was the same as in July 1992. In recent months we have found in July, August, September and October, there has been a certain degree of stabilisation in prices and the wholesale prices of essential food articles are actually lower in November than they were in March this year. Amongst these food articles are wheat, jawar, bajra, arhar moong, urad, mustard oil, groundnut oi and vanaspati. During the financial year from April onwards, the foodgrains price as a whole have declined by 1.4 per cen as against an increase of 14 per cent i the same period last year.

The Government does not accept th view that rise in administered prices, suc as petroleum products, has added to the in flationary spiral although increase i administered price raises the wholesal

price index for that commodity. They also reduce the deficit, which would otherwise be generated if prices are not adjusted, and this reduces pressure of excessive demand in the economy. This rduction in demand pressure has a disinflationary effect on the general level of prices which bcomes evident over a longer period even though the immediate effect may be to raise the index for one commodity.

Excess spending by the Government has been an important factor which some hon. Members have mentioned, particularly Dr. Jain. The Government has taken this factor into consideration. In so far as administered prices are concerned, increases, reduce this excees spending. They serve to break the inflationary spiral rather than reainforcing it. The important point is, there has been no import of consumer goods at the behest of any financial institution including the World Bank mentioned by some friends. Import of certain essential consumer items, such as wheat and edible oil, took place in response to demand, supply and stock position. Such imports do not contribute to inflation. In fact, such imports only increase the supply of these goods and, therefore, reduce the inflationary pressure. In the last financial year, the extremely low level of foreign exchange reserves precluded the import of essential consumables, which had contributed to the higher rate of inflation last year. Conversely, the modest import of consumer goods, especially foodgrains, this year, have helped in stabilising their prices.

Now, Madam, the hon. Member mentioned about the wholesale and consumer price index. Here, I would like to give the figures. In July, 1992, the wholesale price index was 114.9. In October also, it was the same, i.e. 114.9. This trend shows that the wholesale price index has got stabilised.

In the case of consumer price index also, in July, 1992, it was 114.7. In August, there was a slight rise, to 115.5. (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अमीन साहब, आपका रेजोल्यूशन है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप बातों में लगे हुए हैं।

SHRI RAMESHWAR THAKUR : I would like to point out that there has been a decline in the wholesale price index of essential commodities during the current year. I am giving the percentage of decline in November, 1992, over March, 1992, in relation to certain commodities. Wheat—4.1 per cent; jowar-3.1 per cent; bajra-26.7 per cent; arhar-5 per cent; moong-10.4 per cent; urad-3.4 per cent; mustard oil-4.3 per cent; groundnut oil-4.3 per cent; vanaspati-0.6 per cent; salt-2.7 per cent; and long-cloth 2.5 per cent.

Therefore, as you can see from the figures, to say that the prices have gone up would not be a fair proposition. In regard to the consumer price index also, I have the figures for the period April to November.

I now come to the question of inflation. In April, 1991, it was 12.2 per cent. It had gone up slightly higher, in between, in September. In November, 1991, it went down to 13.6 per cent. During the current year, from 14.4 per cent, in April, 1992, it declined to 10 per cent, in September, 1992. Then, it further declined to 8.8 per cent. Today, the information is, it has come down to 8.7 per cent. Therefore, you can see that the inflationary rate which was nearly 17 per cent, in August-September, last year, has come down to 8.7 per cent. It is quite reasonable. Not that we are satisfied with it. We want to reduce it to 4-5 per cent. But it takes time because there are many factors. Unless we are able to increase our production substantially, it will not be possible.

Reference was made by one hon. Member to industrial production. I would like to point out that in the case of industrial production also, we have got a certain degree of increase. From a negative growth last year, this year, during the last six months, it has gone up. Up to September, we have the figure. It has gone up by 2 per cent. This is not much, of course. We want to increase it further.

In the case of GDP also, we are hopeful. The trend indicates that it would be 3.5 per cent during the current year. We expect to achieve a growth rate of 4.5 per cent in industrial production, during the current year.

[SMT. SUSHMA SWARAJ]

The question of resources was also raised. Stress was laid on mobilisation of resources and reduction of Government expenditure. That is why, in the case of budgetary deficit, as compared to 8.4 per cent, in the year 1991, we have brought it down to 6.5 per cent, in 1991-92. The Government's determination is to keep it within 5 per cent during the current year, 1992-93.

This is how the Government is trying to control prices and expenses to the extent possible. Similarly, in the case of revenue collection through effective means in spite of the fact that, as the hon. Member are aware, we have given reduction in our customs and excise duties. From peak rate of 150 per cent we have brought it down to 110 per cent in capital goods we have brought it down from 85 per cent to 55 per cent, giving relief of about Rs. 2500 crores in two items. Similarly, in the case of direct taxes, as the hon. Members are aware, we have raised the limit from Rs. 22,000 to Rs. 28,000, which has enabled 8 lakh assessees to go out of the tax net. Similarly, the peak rate of 50 per cent in direct taxes, that is, income tax, in which we were to lose about Rs. 1500 crores. So, these three items indicated loss of Rs. 4000 crores. Plus, we had the possibility of losing about Rs. 1000 crores in all other small matters, that is, the relief given in the Budget for the current year 1992-93. Madam, we are happy to inform you that in 1991-92 on the revenue side, as compared to 1990-91 year, we have got more collection of Rs. 9465 crores by way of income tax, customs and excise. In the current year, in spite of the substantial reduction about which I have mentioned, up to September 1992, six months, we have experienced a good trend. If we take customs and excise separately, in place of Rs. 21,910 crores we have got Rs. 26,100 crores, an increase of 20 per cent. In the case of direct taxes, in place of Rs. 3300 crores we have got a collection of Rs. 6100 crores, an increase of 81 per cent. This is the collection in the first six months in spite of the substantial reduction allowed in rates.

Therefore, Madam, we are trying our best to increase and augment our revenue resources and by better management we are trying to clear all the arrears. We have given clear directions to be straight, fair and just and that there should be no harassment, no delay.

There are other areas, particularly in the industrial sector, where our investments have started giving results. The real results are yet to come in the coming years. Our firm investments have been about 18 times more up to the period of November 1992. This is increasing. In fact, now we find that actually our one investment is equal to previous one year's investment. This is the situation. We have got the investment of Rs. 29 billion which used to be Rs. 1.6 billion in 1990-91. Therefore, it takes time and the Government is trying seriously and effectively to reduce the expenses, enhance its income and revenue, enhance exports which is more importatnt for our balance of payments situation, have more investment in the field, have deregulation for that purpose and to ensure that in the current year as well as in the coming years we have beter results so that we are able to stabilise the prices. the prices are already slightly stabilised, but we want to reduce them further and efforts in this direction are being made.

With these words, Madam, I conclude.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh) : Madam, I thank you. You have given me time so soon after the Minister's speech. The point here is, he has tried to give us certain figures which we cannot go through all of a sudden, but we know of the figures which have been compiled by the Government itself. I have the three pamphlets which have been given to me by the Lok Sabha Secretariat. One is : "Rising prices of petroleum products", the other is : "External debt of India" and the third is "Emerging inflationary trends". From these bulletins themselves I have picked up certain figures, and also from the newspapers. The point here is, they promised to hold back the prices. But, in fact, the prices are not rolling back. They are only going up, higher and higher. So, what was the promise and what is the result ? That is what we have to take into consideration. So, if we take all these into consideration, the prices are only going

up and up, not coming down. External debt is going up and up and not down. Internal debt is going up and up, not down. So, the troubles of the people are also going up. The point is, people are suffering a lot.

Certain figures are charted out from the files and it is said, now the prices are 0.2 per cent less or 0.3 per cent less. Wholesale prices are going up everyday. Of course, in a particular week they may come down by 0.2 per cent or 0.3 per cent, and then they say, the prices are coming down. But what is the net result of the whole thing ?

Since you came to power last year, we know that the prices went up. You will have to review that. Instead of doing that, what is the use of saying that this week the prices have come down by 0.2 per cent or 0.3 per cent ? What I want to bring to the notice of this House is that the prices are going up. The rate of inflation is worked out in terms of the wholesale prices and not consumer prices. If we take the consumer price into consideration, the rate of inflation worked out, even according to Government figures, to 11.5 per cent in October. So, what is the use of saying that double-digit inflation is not there according to wholesale prices but it has come down to single digit only ? It may have come down, but wholesale prices are not the criteria to consider the troubles of the people.

What are the consumer prices, retail prices ? How are consumer articles selling in the market and how are the people suffering because of the higher prices ? The *Indian Express* has given a review of the whole thing and according to the data supplied by them, between 1991 and 1992, the cost of food articles has gone up from Rs. 650 to Rs. 800 per family. That means, a consumer's family of four members, which is expected to earn about Rs. 1,200 per month, which used to spend Rs. 650 per month on food articles in 1991, is spending Rs. 800 in 1992. whereas they used to spend Rs. 80 on house rent in 1991, they are spending Rs. 100 in 1992. Conveyance charges which used to be Rs. 60 have doubled up to Rs. 120. Like that, a commoner's family of four members is bound to pay Rs. 230 more in the market this year compared to last year, while their income has not gone up like that at all. On the other hand, their income, if calculated in terms of rupees, has fallen down. From the 1981-82 price level, it has gone down to 40 paise rupee. Then where is the income to meet even this much rise in prices.

So, seeing all this, and instead of understanding the Resolution moved by my hon. colleague, Mr. Amin, if you straightway contradict it by saying that the prices have come down by 0.2 per cent or 0.3 per cent, there is no use. So, I want the Government to understand the troubles of the people. - The sufferings of the people are increasing more and more and the number of sufferers is increasing day by day. They say that the number of people living below the poverty line has come down, but it is not at all true. They say that the figures stands at 29 per cent today. When the prices are going up, you take certain schemes that are implemented, and according to the schemes some people are given the benefit of increasing their income. What is the percentage of the people who are getting those benefits through these schemes ? That should be taken into consideration.

So, the rich are growing richer, and the poor are growing poorer. That is a fact of life today. Over the whole country, whether you go to the rural places or to the urban places, you will find this naked truth. So, instead of seeing all these things, if you simple contradict the figures like this, I don't think it is a fair understanding of the whole spirit behind the Resolution. I will read out for your sake, Madam.

"One hundred and sixty million farm workers remain under-employed."

That means, 16 crores of people are under-employed.

> "Some of their families are not getting work for even 280 days in a year. On an average for about 80 days they are getting work."

Here again :

> "Women work harder but are underpaid."

[SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO] This is a figure from the ILO. Taking into consideration the Indian conditions, the ILO has given this figure.

"Dark Diwali for jobless workers." This I have picked up from "THE HINDUSTAN TIMES" on the Diwali Day. What does the correspondent say therein? He went to Ahmedabad, Gandhiji's place where Gandhiji had started his trade-union movement. What is the fate of the workers there?

> "More than 40,000 workers have been rendered jobless with the closure of 30 textile mills in the past decade, and their ranks are likely to swell with the additional of nearly 15,000 workers following the closure of 8 NTC mills more."

The point is : As a result of this, what is the social consequence? The social consequence is :

> "Boys have started doing sundry jobs, while grownup girls in some cases have taken to prostitution."

What a horrible situation there is in Gandhiji's place! Suicides and so many other things have taken place.

> "Women have shed their inhibition and started working as casual workers in factories and godowns."

This is the report of "THE HINDUSTAN TIMES" correspondent from Ahmedabad. So, like that, if we go by the price reports that are coming out everyday, we will find that people are suffering in a hopeless manner. Without taking that into consideration, if you simply deny what we say, there is no meaning in that.

My friend, Mr. Narayanasamy, has been saying that for all these evil consequences, the brief period of one year of the Janata rule or the National Front Government rule was responsible. It is a very partial understanding. This understanding won't go well. He might try just to juggle words at us. But, the point is : Can he convince the people by all this? The question is this.

I have got the figures about petroleum products. The figures for the gas cylinder since 1975 are here. Fifteen kilogram cylinder in 1975 used to cost Rs. 23.94. Under the National Front Government, its price was kept at Rs. 57.44. This price was kept at the same level for three to four years, though the war was there in those days. But what is the price of the cylinder now? When this figures were given its price was Rs. 86. Its price went up further and now it is Rs. 92. How do you justify all this? It is a commodity used generally by all people here and they are suffering because of its price increase. About the petroleum products also you say the National Front Government had increased its price and had put it at a higher level. So, you are following it. Is it a justification? If you go through the index of the petrol price over the years you will find that as on 1-1-1973, it was Rs. 1.41 paise a litre. Now as on 16-9-1992, its price had gone up to Rs. 18.38 paise. Since this Govenrment has taken over, its price has gone up from 13.81 paise to Rs. 18.38. Roughly an increase of Rs. 5 had taken place. I am not going into the details of paises. This increase had taken place without war being there. So, you cannot just explain away that the increase had taken place because of the war.

Because of the administered prices of the petroleum goods having been increased, price of every other article has gone up and it has affected the Staes economy also. In our own State of Andhra Pradesh milk price has gone up, power price has gone up and the bus transport price has also gone up. Everything is sought to be increased by explaining that the petrol price has gone up. This is the explanation from the top to the bottom given by the ruling party and also by my hon. friend, Shri Narayanasamy. However much you want to close your eyes, the facts are there to see that your eyes are opened. That is why I say that we will have to appreciate the mover for bringing forward this Resolution before us; and we will have to unanimously support it in order to prevail upon the Government to take some more serious steps in order to bring down the prices. That is to be done. Thank you.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम माननीय सदस्य मोहम्मद अमीन साहब यह संकल्प जिस विषय पर लाए हैं, यह बहुत चिन्ता का विषय है और इसके लिए सरकार को दोषी मानें या व्यवस्था को दोषी मानें या इस देश के लोगों को दोषी मानें, हमें पहले यह तय करना पड़ेगा कि इस महंगाई के लिए कौन दोषी है ? इसकी चिन्ता इस सदन के सदस्यों को भी है · · ·

एक माननीय सदस्य : दोषी जो भी हो, बढ़ी है या नहीं ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : बढ़ी हुई मान रहे हैं, तभी तो दोष का सवाल आया।

श्री मूल चन्द मीणा : महंगाई की बात जरूर हम यहां करते हैं लेकिन इस बात को भी जानते हैं कि यह महंगाई क्यों बढ़ रही है। कुछ राजनीतिक दल तो नाटक ही कर लेते हैं महंगाई के खिलाफ आंदोलन करके। लोगों को यह दिखाने के लिए कि हम महगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि महंगाई के लिए दोषी कौन है। इस वैज्ञानिक युग के अंदर एक अल्प वेतन भोगी और मध्यम वर्ग की जो क्रय शक्ति है वह सुरसा की तरह अपना मुह फैलाना चाहती है लेकिन · · ·

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : क्रय शक्ति अगर सुरसा की तरह मुंह फैला ले तो फिर सारे काम का निदान ही हो जाए।

श्री मूल चन्द मीणा : क्रय शक्ति मैं कह रहा हूं लोगों की इच्छा शक्ति · · ·

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : खरीदने की ताकत अगर सुरसा की तरह मुंह फैला ले तो · · ·

श्री मूल चन्द मीणा : आपने सुना नहीं बीच में कह रही हैं महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : यह कहिए इच्छा शक्ति।

मूल चन्द मीणा : इच्छा शक्ति है क्रय करने की। जो अल्प वेतन भोगी हैं, मध्यम - वर्ग के लोग हैं उनकी इस वैज्ञानिक युग के अंदर टी० वी० को खरीदने की इच्छा करती है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : खरीदने की इच्छा शक्ति कहिये।

श्री मूल चन्द मीणा : खरीदने की इच्छा शक्ति लोगों की है। अल्प वेतन भोगी, मध्यम वर्ग के आदमी रोज के काम में सुख-सुविधा के लिए · · ·

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : इसके लिए यह कहिये कि क्रय की इच्छा, खरीदने की इच्छा शक्ति सुरसा की तरह मुंह फैलाये खड़ी है।

श्री मूल चन्द मीणा : मैं यही कहना चाह रहा था। जिस प्रकार से क्रय की इच्छा शक्ति है उसको यह महंगाई कितनी बौनी बना रही है। इसके वास्तविक आधार पर हम जायें तो सरकार भी कोशिश करती है महंगाई कम हो लेकिन हो इसका उलटा रहा है। यहां की जो व्यवस्था है उनका कंट्रोल नहीं। वैसे भी यह व्यवस्था स्टेटों के हाथ में है। हमारे सामने बैठने वाले सदस्य केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिए दोषी मानते हैं · · ·

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : और किस को कहें ? वह तो है ही।

श्री मूल चन्द मीणा : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसके लिए स्टेटों के अंदर जो सरकारें हैं वह भी दोषी हैं इसके साथ। वह नहीं कहते हैं आप लोग। आज की स्थिति यह है। मैं राजस्थान का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। गांव के आदमी को, गरीब मजदूर को खाने का सामान

[श्री मूल चन्द मीणा]

उपलब्ध कराने के लिए इस देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरसिंह राव जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बाड़मेर के अंदर दुकाने खुलवाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में किस की सरकार है और उस वितरण प्रणाली को लागू करने और कंट्रोल करने का अधिकार किस का है? क्या वहां पर वितरण प्रणाली सही रूप से चल रही है? लोगों को माल मिल रहा है? गरीब को, किसान को और मजदूर को सही सस्ते दर पर, गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पर माल मिल रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो ह्रास हो रहा है इसके लिए हम केन्द्रीय सरकार के सर पर दोष मढ़ते हैं। यह गलत बात है। खाद्य पदार्थों की बात को लें। इसमें तेल को ले लें, साबुन को ले लें, गेहूं को ले लें, चीनी को ले लें। कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी नहीं हो रही है।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें क्या राज्य सरकारों ने बढ़ाई है?

श्री मूल चन्द मीणा: मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए फिर पूछना पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स की कीमतें कैसे बढ़ी? मैं पेट्रोल की ही बात कर लेता हूं। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी। खाद के ऊपर सबसिडी थी, खाद की कीमत बढ़ी। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज): दवे जी व्यवधान मत डालिए। इनको बोलने दीजिए। उसके बाद आप बोलना चाहते हैं तो अपना नाम दे दीजिए अगली बार बोल लीजिएगा लेकिन व्यवधान मत डालिए। सदन को सुचारू रूप से चलने दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा: तेलों की कीमतें बढ़ी थीं, पेट्रोल और खाद की कीमतें बढ़ी। तेल की कीमत तो एक निश्चित डे को बढ़ी, लेकिन खाद्य तेलों और डीजल पहले से ही महंगा क्यों बेचा गया? क्या इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। खाद की कीमत बढ़ी, लेकिन राज्यों की सरकारों ने उस पर कंट्रोल नहीं किया। खाद विक्रेताओं के पास जो खाद थी, यदि वे उसको उसी रेट पर बेचते तो किसानों को नुकसान नहीं होता। किसानों को साढ़े पांच सौ और पांच सौ रुपये में एक बेग मिला था। क्या इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था? जिस दिन खाद की सबसिडी को खत्म किया गया था उस दिन यह पूछा गया कि आपका कितना कोटा है, कितने खाद की मात्रा है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो आज यह कह रहे हैं कि तेल की कीमत केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाई, लेकिन राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निर्देश के बाद भी कि आपके पास खाद का भंडार क्या है, उसके 15 दिन के बाद ही राज्य सरकार ने खाद विक्रेताओं से पूछा कि आपके पास कितना भंडार है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि इस सब के लिए केन्द्रीय सरकार ही दोषी है। इसके अन्दर राज्य सरकार की व्यवस्था भी दोषी है।

आज महंगाई की बात की जा रही है। इसके लिए सबसे बड़ा दोष इस देश के अन्दर राष्ट्रीय चरित्र का है। आज लोगों का चरित्र लूट-खसोट का बन गया है, लूटने का बन गया है, खून चूसने का बन गया है। इन लूट-खसोट करने वालों को कौन सपोर्ट करता है? यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। आज आप साबुन की बात को लें। पहले साबुन चार रुपये में मिलता था, लेकिन उसकी कीमत अब 6 रुपये हो गई है और उसका साइज भी

कम हो गया है । लोगों को जो असली माल मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता है, नकली माल मिलता है । लेकिन चिन्ता का विषय इस राष्ट्र में यह है कि सरकार को कीमतों पर कंट्रोल करना चाहिए । जमाखोर लोग जो सामान जमा कर लेते हैं उनका सामान बाहर निकाला जाना चाहिए और उस पर कंट्रोल होना चाहिए । आज आपकी जो कंट्रोलिंग व्यवस्था है स्वतंत्र आर्थिक बाजार की व्यवस्था है इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए जिससे लोगों को सही रेट पर सामान मिल सके । एक जमाना था 1975 का, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमरजेंन्सी लगाई थी तो इन जमाखोरों ने अपना माल बाहर फेंक दिया था । उस समय यह कंट्रोल था । उस समय एक भय था । आज कोई भय नहीं है । बसों के किराये में वृद्धि की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत बंद करने का आवाहन करते है, राजनैतिक नाटक करते है । लेकिन मैं पश्चिमी बंगाल के लोगों की दाद देना चाहता हूं कि वहां अगर बसों के किराये में या ट्रामों के किराये में 10 पैसे की भी वृद्धि की जाती है तो वह सब खड़े हो जाते है । लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह से नाटक नहीं करते है । आज अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी के लिए जीना दुश्वार हो जाएगा । आज रोटी और दाल के लिए महंगाई अड़ंगा लगा रही है । लोग भूखों मर जाते है । उनको खाना नहीं मिलता है । गांधी जी का सपना था कि एक अच्छे चरित्र के साथ भारत की उन्नति और विकास हो, गरीबों को राहत मिले । गरीबों को ऊंचा उठाना लेकिन आज इन गरीबों के विकास के नाम पर एक वर्ग जो पहले सम्पन्न था वह पहले से ज्यादा सम्पन्न हो रहा है ।

एक बात और आई कि पिछले चुनाव के अंदर, गये चुनाव के अंदर कांग्रेस ने वायदा किया था कि सौ दिनों में हम महंगाई कम कर देंगे । लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कभी मंडल, कभी मंदिर और कभी कर्ज माफी के नाम पर कुछ पार्टियां सत्ता में आ जाती है । ऐसे लोगों ने इस देश को दिवालियापन के कगार पर खड़ा कर दिया । इन लोगों ने, यहां तक कि इस देश का सोना भी दूसरे देशों के अंदर गिरवी रख दिया और आज वही लोग कहते है कि कांग्रेस ने वायदा किया था कि महंगाई कम कर देंगे । सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता होता है कि देश की अर्थ व्यवस्था क्या है । हमने देश की अर्थ व्यवस्था को किस तरह से कंगाल कर दिया है, यह ऊपर बैठे हुए लोगों को पता रहता है । जिस स्थिति में देश 1989 में था, कांग्रेस ने वही स्थिति समझी थी कि इस प्रकार की देश की अर्थ व्यवस्था होगी । इसलिए कांग्रेस ने यह वायदा किया था । लेकिन जब हमने अंदर घुसकर देखा तो देश को दिवालिया पाया । उस अर्थ व्यवस्था को ठीक करने में डेढ़ वर्ष लग गये तब देश की अर्थ व्यवस्था कुछ ठीक हुई, यह आप लोग भी मानते हैं । देश के अंदर महंगाई कम करने के लिए कदम तभी बढ़ाया जा सकता है जब अपने पास पूंजी हो, धन हो।

मैडम, यह जो संकल्प अमीन साहब लाये हैं, मैं उनकी चिन्ता से सहमत हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि महंगाई कम करने के लिए हमारी जो मिलें बंद पड़ी हुई हैं, जो उत्पादन कम हो रहा है, उसको बढ़ाया जाए, बड़े उद्योगों को दी जाने वाली सबसिडी को बंद किया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो इस देश की है उसको सुदृढ़ किया जाए, स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल किया जाए, तभी हम इस महंगाई पर पार पा सकते हैं । महोदया, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद ।

*DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Madam Vice Chairperson, to-day every Indian women especially the housewife is wishing three things. Her first wish is that our finance Minister should not go to the World Bank for loan. This is her first wish which she asks for while praying to God. Her second wish is that the sun should never rise the next morning. This is her prayer every night before she goes to bed. Her third wish is that she should have the 'Akshaya Patra' wish Draupadi had in Mahabharata. These are the three wishes of an Indian house-wife.

Let us know the reason of her wishes. Her first wish that the Finance Minister should not go to the World Bank for loan. She knows that if the Finance Minister Goes to Washington or any other foreign country it is only to borrow some money. When he visits a foreign Country he has to submit to their unconditionalities. They ask him to increase the prices of some Comodities, harrass our people which they enjoy and only then they relent and sanction some loan. So each visit of the Finance Minister to a foreign country is followed by an increase in our prices resulting in further increase in the worries of the people of our coutry.

Her second wish is that the sun should not rise the next moruing because her problems start as the day begins. She has to start cooking every morning. Cooking means consumption of LPG. Fear clutches at her heart as soon as she thinks that LPG Cylinder is going to be exhausted and she will have to get another Cylinder. Her day starts with a fear. She somehow manages to overcome this fear and lights the oven and starts boiling some Water. Now comes the turn of Sugar, tea leaves or coffee powder which she has to use for the morning cup of tea or coffee. She uses it sparingly with a fear that she has to purchase it again Finally she completes the coffee session. Next comes the problem of sending children to school. She finds that the bus fares have increased due to a hike in the prices of petrol. She will find an increase in the school fees. So each morning brings with it added problems. That is why she wishes to spend her time in sleeping because that is the only time she has not to face any problem. But since this is an unfulfilled wish, she prays to God to give her an 'Akshaya Patra' as the one Draupadi had. She feels that if she also has one she can feed her children and also the relations and guests who visit her home.

Next comes the turn of man. He is scared to go to take pocket full of money and get a bag full of things. But now even if we takes a bag full of money he is not able to bring even a pocket.

Madam, what did the Congress Party say in their manifesto? They had promised to bring the price-level back to July 1990 position. The gullible people believed their commitments and voted them tc power and now they feel cheated. Now the people are crying aloud saying that they need not bring the prices back to 1990 prices but just see that they do not increase any further. They are continuously devaluing the rupee. They are always trying to borrow from the foreign countries at the cost of devaluing our rupee. To-day we have to pay a loan of Rs. 2,50,000 crores. To repay this loan we have to pay a minimum of Rs. 18,000 crores every year. We have to pay this in dollars. We have to increase our exports to get more foreign exchange. But where is the capacity for us to increase our exports? Al this is directed against the common mar and he has to bear the burden of increasec prices.

Madam, our government talks of defici budget. Earlier the prices used to in crease once a year, i.e. after the presenta tion of the budget. But now every da the prices are increasing. The budget ha become totally irrelevant. This is th present situation. While the prices o petrol are decreasing in the internaiona market, they are increasing in our countr day by day.

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMAT SUSHMA SWARAJ) : Now, the tim allotted for the Private Members' Busines is over. We wil continue this Resolutio on next to next Friday, that is, on 18 Now, we shall take up the Special Mer tions.

*English translation of the original speech delivered in Telugu.